SHARMA
HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in

हिंदी दैनिक

गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 12 | अंक : 349 | गुवाहाटी | शनिवार, 25 जुलाई, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

पूरी पार्टी खड़ी है धर्मेंद्र प्रधान के साथ : सरकारी सूत्र पेज 2
असम बाढ़ : 11 जिलों की 7 लाख आबादी प्रभावित, छह और शव मिले पेज 3
कांग्रेस देश के युवाओं को गुमराह कर सेंक रही है राजनीतिक... पेज 5
भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुआ ग्लास्गो कामनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज पेज 7

असम में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर, सामान्य से 400 फीसदी अधिक वर्षा बनी बड़ी वजह : सीएम

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सामान्य से 400 प्रतिशत अधिक वर्षा इस भीषण बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को लोक सेवा भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बाढ़ प्रभावित उपरी असम के जिलों का दो दिनों तक दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री ने आज गुवाहाटी पहुंचकर बताया कि शिवसागर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 20 प्रतिशत और नाजिरा विधानसभा क्षेत्र के करीब 30 प्रतिशत हिस्सों तक प्रशासन अब भी नहीं पहुंच सका है। सड़क संपर्क पूरी तरह टूट जाने के कारण राहत सामग्री भेजने में भी कठिनाई हो रही है, हालांकि प्रशासन प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से लोगों के घरों, पशुधन और आजीविका को भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल नुकसान का सही आकलन करना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि एवं पशुपालन मंत्रियों को अगले तीन दिनों के भीतर प्रभावित जिलों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने हालिया बाढ़ के दौरान लखीमपुर और धेमाजी जिलों को बड़े नुकसान से बचाने में एनएचपीसी की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डॉ. शर्मा ने लोगों से बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकारी, निजी और सामूहिक सहयोग राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा सभी को एकजुट होकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए।

जोरबाट में पहाड़ियों की अनियंत्रित कटाई से *अव्यवस्थित* हो सकता है गुवाहाटी : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी। असम सरकार ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि जोरबाट के आसपास अनियंत्रित विकास और पहाड़ी कटाई से गुवाहाटी को गंभीर खतरा है, और कहा कि पहाड़ियों से बहकर आने वाला पानी भूस्खलन और शहरी बाढ़ को बढ़ा रहा है और शहर को *अनियंत्रित* कर सकता है। राज्य में बाढ़ से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दिसपुर के लोक सेवा भवन में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि यह मुद्दा पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है और अदालत द्वारा नियुक्त अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों के आधार पर इस पर बहस की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति ने इस मामले की जांच की है और उन्होंने एक बेहद भयावह रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि जोरबाट में, विशेष रूप से यूएसटीएम और आसपास के क्षेत्रों में विकास, गुवाहाटी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगा, शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गुवाहाटी में देखी गई बाढ़ और जलभराव की घटना सीमा के मेघालय की -शेष पृष्ठ दो पर

10 साल की सजा, 10 करोड़ जुर्माना...

पेपर लीक संशोधन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक के प्रदर्शन के बीच कैबिनेट बैठक ने पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और सख्त बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी गई। सरकार अगले सप्ताह में मानसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है। इस बिल में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। बिल में पेपर लीक के मामलों में 10 की सजा और 10 करोड़ के जुर्माना का प्रावधान होगा। पेपर लीक विवाद और प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया था। पीएम मोदी ने 2.56 मिनट का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। यह लाखों छात्रों और -शेष पृष्ठ दो पर

एनटीए ने 47 अधिकारियों को नौकरी से हटाया

नई दिल्ली (हि.स.)। पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में आई उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा संचालन करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने 47 अधिकारियों को नौकरी से हटाया है। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 47 अधिकारियों को उनकी सेवा से हटा दिया है। इनमें से कुछ -शेष पृष्ठ दो पर

सरकार के लिखित आश्वासन पर सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन

नई दिल्ली (हि.स.)। पर्यावरणविद् एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार तड़के 26 दिनों से जारी अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों से लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। सरकार ने संसद में नीट प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और शिक्षा सुधार पर विस्तृत चर्चा कराने, हालिया नीट प्रश्नपत्र लीक से जुड़े आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को उपयुक्त मुआवजा देने तथा जंतर-मंतर और 20 जुलाई के संसद मार्च में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों एवं युवाओं के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करने का आश्वासन दिया है। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान -शेष पृष्ठ दो पर

Government of Assam
Finance Department

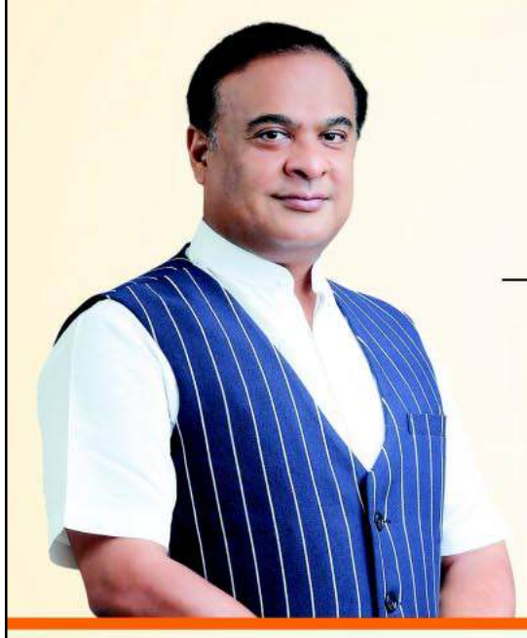

Doorstep Banking Services
for senior citizens (70+) and Differently abled/infirm persons

- Digital Life Certificate for Pensioners
- Cash, instrument pickup & delivery
- Withdrawals
- Demand draft delivery
- Submission of KYC documents

Dr Himanta Biswa Sarma
Chief Minister, Assam

Jeevan Pramaan
Ensuring Dignity, Transparency and Seamless Pension Delivery

Nodal Officers for Pension Disbursing Banks

Name	Bank	Contact number	Name	Bank	Contact number
Shri Ganesh Kumar Roy	Indian Overseas Bank	9871777520	Shri Durlav Taye	India Post Payment Bank	9864232376
Shri Satyam Kumar Thakur	Punjab National Bank	9593344467	Shri Nabarun Dey	Bank of Maharashtra	9831297876
Shri Uddipjyoti Rongkho	Punjab & Sind Bank	9853055910	Shri Tanmoy Kishore	Bank of India	7002060658
Shri Ram Kumar Chettri	State Bank of India	9435481282	Shri Ajeet Kumar	Canara Bank	7099072894
Shri Binod Kumar	UCO Bank	8461903247	Shri Dharmendra Kumar	Central Bank of India	8758543645
Shri Prabir Sen	Union Bank of India	9854572269	Shri Ripunjit Borah	HDFC	9864523604
Shri Kushal Kishore	Bank of Baroda	8100037276	Shri Rajat Sinha	Indian Bank	9473431027
Shri Sridhar Gogoi	Bandhan Bank	9678004342			

In case of non-compliance, contact Nodal Officer in Finance Department
Ajit Das, Director of Accounts & Treasuries, Assam 9435086352

-- DIPR /D/VBS-41/25-Jul-26

Published by Directorate of Information and Public Relations, Assam
Connect with us @diprassam dipr.assam.gov.in

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
94350-14771

प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं : सीजेपी

नई दिल्ली (हि.स.)। सरकार के साथ यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमारी इस मांग पर सरकार ने शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह शामिल थे, जबकि सीजेपी का प्रतिनिधित्व आशुतोष रांका और सौरव दास ने किया।

आज से नगांव-मोरीगांव में कांग्रेस की प्रतिनिधि बैठक

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) की दो महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बैठकें 25 और 26 जुलाई को क्रमश: नगांव और मोरीगांव जिला कांग्रेस कार्यालयों में आयोजित होंगी। बैठकों में राज्य के ज्वलंत मुद्दों, बाढ़ राहत कार्यों में कथित सरकारी विफलता तथा शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं पर चर्चा की जाएगी। एक बयान में कहा गया है कि इन बैठकों में बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा, प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पार्टी की रणनीति तथा नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अभियान पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

व्यवस्था में होगा सुधार, पद छोड़ना नहीं है समाधान

पूरी पार्टी खड़ी है धर्मेंद्र प्रधान के साथ : सरकारी सूत्र

नई दिल्ली। नीट-यूजी पेपर लीक बवाल के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकारी सूत्रों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस्तीफा देना? नो चांस! सूत्रों के मुताबिक, इस्तीफा देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना और मैदान छोड़कर भागना तो सबसे आसान काम है। जनता ने हमें जनादेश दिया है काम करने के लिए, और हम काम करके दिखाएंगे-भागेंगे नहीं। सूत्रों के अनुसार, सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से पीछे हट जाना सबसे आसान रास्ता है। जनता ने सरकार को जनादेश दिया है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था में सुधार करेगी। पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। यह घटनाक्रम कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के लिए एक बड़ा झटका है, जो जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और नीट पेपर लीक विवाद व परीक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। सूत्रों ने बताया कि सरकार दिखावटी कदम उठाने के बजाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की व्यवस्थागत कमियों को दूर करने पर ध्यान दे रही है। परीक्षा आयोजित करने वाली इस संस्था की कमियों की एक विस्तृत सूची तैयार की गई है और उम्मीद है कि जल्द ही सुधार के उपाय लागू किए जाएंगे। सूत्रों ने पेपर लीक नेटवर्क के खिलाफ सरकार की जारी कार्रवाई का भी जिक्र किया और बताया कि परीक्षा के पेपर लीक करने वाले कई गिरोहों का पर्दाफाश किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नीट पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सीजेपी ने फिर से दोहराया कि प्रधान का इस्तीफा एक ऐसी मांग है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। शुक्रवार को विट्ठलभाई पटेल हाउस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ हुई दो घंटे की बैठक में, सीजेपी के प्रतिनिधियों ने सरकार से कहा कि वे प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। संगठन ने सोमवार को हुए *संसद चलो* मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस बर्बरता के लिए केंद्र सरकार, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सार्वजनिक माफी की भी मांग की। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि संगठन ने 3 मई की नीट परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और परीक्षा सुधारों पर अपने पांच-सूत्रीय चार्टर को स्वीकार करने की भी मांग की। सरकार को सौंपे गए एक पत्र में, सीजेपी ने कहा कि उसने देश भर में अपने समर्थकों और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बाद यह तय किया है कि उसकी मांगें - जिनमें प्रधान का इस्तीफा, नीट पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजा और प्रदर्शनकारियों को कानूनी कार्रवाई से छूट शामिल है - ऐसी हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और तेज होगा और पूरे देश में फैल जाएगा।

रास में राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने वाला विधेयक पेश

संसद के दोनों सदन सोमवार तक स्थगित

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने शुक्रवार को राज्यसभा में राष्ट्रगीत *वंदे मातरम्* को राष्ट्रगान के समान दर्जा दिलाने वाले वाला विधेयक पेश किया। नित्यानंद राय ने सदन में आरोप लगाया कि विपक्ष विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को भी सम्मान प्राप्त होगा। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों का समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में शुक्रवार को भी विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज प्रभावित रहा। लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्यवाही की शुरुआत में करगिल दिवस (26 जुलाई) पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे और बाद में सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरी ओर राज्यसभा में पहले कार्यवाही 12 बजे, फिर 02 बजे और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में दोपहर 2 बजे कार्यवाही प्रारंभ होने पर नित्यानंद राय ने सदन में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन किए जाने वाला विधेयक पेश किया। विधेयक को पेश किये जाने का सीपीआई नेता संदोष कुमार पी और सीपीआई (एम) नेता जॉन ब्रिटास ने विरोध किया। ब्रिटास ने कहा कि संसद साधारण कानून बनाकर संविधान की मूल व्यवस्था को नहीं बदल सकती। संविधान सभा ने लगभग तीन वर्षों के गहन विचार-विमर्श के बाद जानबूझकर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को समान संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। यदि संविधान निर्माताओं की ऐसी मंशा होती तो वे इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करते। उन्होंने कहा कि कानून के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रवाद को गढ़ा नहीं जा सकता। इस विधेयक का उद्देश्य समाज का ध्रुवीकरण करना प्रतीत होता है। संदोष कुमार ने कहा कि भारतीयों को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। रवींद्रनाथ ठाकुर सहित भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इसे समझा था। यही कारण है कि राष्ट्रगान के केवल दो अंतरों को ही अपनाया गया। वे इस विधेयक का विरोध करते हैं कि इसके माध्यम से रवींद्रनाथ ठाकुर और बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के बीच कृत्रिम विभाजन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच लोकसभा में संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर विपक्ष से छात्रों के मुद्दे पर चर्चा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को आश्वासन दिया है और सामाजिक कार्यकर्ता (सोनम वांगचुक) ने भी भूख हड़ताल समाप्त कर चर्चा की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को इस विषय में समझाएं। इससे पहले सुबह 26 जुलाई को रविवार होने के कारण करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है।

शिक्षामंत्री का इस्तीफा समेत तीन मांगों से कोई समझौता नहीं करेगी कांग्रेस : राहुल

नई दिल्ली (हि.स.)। नीट प्रश्नपत्र लीक मुद्दे पर संसद में चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस तीन मांगों पर अड़ी है, जिनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के दोषियों पर कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों से माफी की मांग शामिल है। हम इन मांगों से कोई समझौता नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने उनसे कहा कि चर्चा होने दी जाए। जब वह जवाब देना चाह रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का रुख स्पष्ट है। पहली मांग है कि भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना चाहिए। दूसरी मांग है कि जिन लोगों ने छात्रों पर हमला किया, उन पर कार्रवाई और जवाबदेही तय होनी चाहिए। तीसरी मांग है कि प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा है और कांग्रेस इस पर कोई समझौता नहीं करेगी।

अमेरिका ने भारत, पाकिस्तान समेत 60 देशों पर 10-12.5 प्रतिशत तक लगाया टैरिफ

वॉशिंगटन (हि.स.)। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने की घोषणा की है। यह फैसला शुक्रवार से प्रभावी हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्देश पर अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात को लेकर भारत समेत 60 देशों पर यह कार्रवाई की है। इन देशों पर 10 से 12.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत 17 देशों पर 10 प्रतिशत और 43 देशों पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने यह कार्रवाई ट्रेड एक्ट-1974 की धारा 301 के तहत की है। नया अतिरिक्त आयात शुल्क गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात 12.01 बजे से प्रभावी हो गया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्रिटेन, कंबोडिया, कनाडा, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, श्रीलंका और त्रिनिदाद एवं टोबैगो पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क तय किया गया है। वहीं, यूरोपीय संघ, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड के लिए ऐसी दरें तय की गईं, जिन्हें पहले से मौजूद *मोस्ट-फेवर्ड-नेशन* टैरिफ दरों के साथ जोड़ने पर कुल दर 10 प्रतिशत या 12.5 प्रतिशत हो जाएगी। बाकी 38 देशों के लिए 12.5 प्रतिशत की दर तय की गई। इनमें चीन भी है, जिस पर अमेरिका ने उइगर *अल्पसंख्यकों* को कर्क कैंप में रखने का आरोप लगाया है, हालांकि बीजिंग इससे इनकार करता है। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब ठीक इसी समय 10 प्रतिशत का अस्थायी ग्लोबल टैरिफ भी

मणिपुर हिंसा पर एससी सख्त, जांच में तेजी और विशेष अदालतों के गठन के दिए निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर में 2023 में हुई जातीय हिंसा से संबंधित आपराधिक मामलों की प्रतिदिन सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही जांच एजेंसियों को मामलों में लंबित जांच शीघ्र पूरी करने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि पीड़ितों को चार्जशीट की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि कई पीड़ितों और उनके परिवारों को सीबीआई व राज्य एसआईटी की ओर से दाखिल आरोपपत्रों की प्रतियां अभी तक मुहैया नहीं कराई गई हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि विधिक सहायता वकीलों के संपर्क करने के एक सप्ताह के अंदर जांच एजेंसियों को उन्हें आरोपपत्रों की प्रतियां उपलब्ध करानी होंगी। हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़ितों की ओर से पेश विधिक सहायता वकीलों को आरोपपत्रों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए गौहाटी हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कार्यालयों से संपर्क करने की अनुमति दी।

लाहौल स्पीति में पहाड़ी से गिरी चट्टान की चपेट में आई टाटा सुमो, 13 लोगों की मौत, दो घायल

शिमला (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। उदयपुर थाना क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की मुख्य सड़क पर कढ़नाला-राहौली के पास पहाड़ी से अचानक गिरी भारी चट्टान की चपेट में एक टाटा सुमो आ गई। हादसे में वाहन में सवार 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को बचाकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के बाद पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस के अनुसार, टाटा सुमो (एचपी-01एम-2210) में चालक सहित कुल 15 लोग सवार थे। वाहन को बीर सिंह चला रहे थे। कढ़नाला क्षेत्र में राहौली के पास पहुंचते ही पहाड़ी से अचानक बड़ी चट्टान नीचे आ गिरी।

वाहन सीधे उसकी चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही अधिकांश यात्रियों की मौत हो गई। चट्टान गिरने से वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। लाहौल स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि हादसे में वाहन में सवार 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि दो लोग घायल हुए हैं और उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि हादसा चंबा जिले के पांगी और लाहौल स्पीति जिले के सीमावर्ती इलाके में हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी मृतक चंबा जिले के पांगी क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि जिला लाहौल की पुलिस चौकी तिंदी और उदयपुर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मृतकों की पहचान की जा रही है। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा। यह हादसा ऐसे समय हुआ है, जब प्रदेश में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के बीच प. बंगाल से वापस बुलाई गई केंद्रीय बल की 20 अतिरिक्त कंपनियां

कोलकाता (हि.स.)। दिल्ली में सीजेपी और विभिन्न दलों के विरोध-प्रदर्शनों और संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 20 अतिरिक्त कंपनियों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया है। इसके साथ ही बख्तरबंद वाहनों को भी सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने 21 जुलाई की रात इन कंपनियों की तैनाती का आदेश जारी किया, जिसके बाद गुरुवार रात को कोलकाता से सीआरपीएफ के जवानों को विशेष व्यवस्था के तहत दिल्ली रवाना किया गया।

मप्र में फिर गरमाया भोजशाला विवाद चालीसपीर दरगाह पर नहीं हुई जुमे की नमाज

धार (हि.स.)। मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गरमा गया है। यहां शुक्रवार को प्रशासन द्वारा निर्धारित मालीवाड़ा में चालीसपीर दरगाह के पास जुमे की नमाज अदा नहीं की गई। मुस्लिम पक्ष नमाज के लिए भोजशाला के पास वाली जगह देने की मांग पर उड़ा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने बीती 14 जुलाई को मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए भोजशाला के पास जगह उपलब्ध कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए थे। न्यायालय ने कहा था कि हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान मुहैया कराया जाए। इसके बाद जिला प्रशासन ने मालीवाड़ा गांव में चालीसपीर दरगाह के पास नमाज की जगह निर्धारित की थी लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसी को लेकर गुरुवार देर रात जिला प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच करीब दो घंटे तक चली बैठक में अन्य संभावित स्थानों का प्रस्ताव रखा गया लेकिन नमाज के वैकल्पिक स्थान को लेकर सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते शुक्रवार को प्रशासन द्वारा निर्धारित मालीवाड़ा में चालीसपीर दरगाह के पास जुमे की नमाज अदा करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस की ओर से मौके पर सभी इंतजाम किए गए थे। मुस्लिम समाज का कहना है कि उन्हें उनके पारंपरिक स्थान पर ही नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। धार के सदर अब्दुल समद ने कहा कि प्रशासन उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। जब भोजशाला परिसर में नमाज होती थी, तब भी कभी कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ी। नमाज बंद होने के बाद भी कोई विवाद नहीं हुआ इसलिए इतनी दूर वैकल्पिक व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि चालीसपीर दरगाह के पास निर्धारित स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसके बजाय जुमे की नमाज आसपास की मस्जिदों में अदा की जाएगी। सदर ने पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि इससे पहले 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर प्रशासन ने जिस जगह पर उमी नमाज कराई थी, वह दरअसल कब्रिस्तान की जमीन है।

पृष्ठ एक का शेष

जोरबाट में पहाड़ियों की ...

ओर चल रही विकास गतिविधियों से निकटता से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आज गुवाहाटी जिन भी समस्याओं का सामना कर रहा है, वे जोरबाट और उसके आसपास के विकास के कारण हैं। यूएसटीएम तो बस शुरुआत है; यूएसटीएम के पीछे जो हो रहा है वह कहीं अधिक खतरनाक है, जिसमें पहाड़ियों का बड़े पैमाने पर विनाश शामिल है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि मेघालय की पहाड़ियों से बहकर आने वाले जल के कारण लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब मेघालय सरकार ने प्रदूषण के कारण बायर्नीहाट में कुछ गतिविधियों पर रोक लगा दी है। मुझे लगता है कि उन्हें असम पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जोरबाट के पास विकास को विनियमित करने के लिए पड़ोसी राज्य से अपील करते हुए, शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि पहाड़ी का विनाश जारी रहा तो गुवाहाटी में बहने वाले पानी की मात्रा को संभालने में कोई भी जल निकासी अवसंरचना सक्षम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं मेघालय सरकार से केवल यही अपील करूंगा कि जोरबाट और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास को नियंत्रित करने के उपाय तलाशें। अन्यथा, गुवाहाटी एक अनियंत्रित शहर बन जाएगा। हम शहर को संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि यहां आने वाले पानी को किसी भी प्रकार की जल निकासी व्यवस्था से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। शर्मा ने कहा कि वह इस मामले पर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा के संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मेघालय की अपनी विकास प्राथमिकताएं भी हैं। उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि उन्हें भी विकास की जरूरत है और पूछते हैं कि केवल असम का ही विकास क्यों होना चाहिए। उनके अपने तर्क हैं। मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। स्थिति को भौगोलिक चुनौती बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असम, एक निचले मैदानी राज्य होने के नाते, पड़ोसी पहाड़ी राज्यों में होने वाले विकास के परिणामों को अनिवार्य रूप से भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यही विरोधाभास है। असम एक मैदानी इलाका है, और अन्य राज्यों में होने वाले विकास का प्रभाव अंततः यहीं पड़ेगा। गुवाहाटी में बार-बार आने वाली बाढ़ के बारे में शर्मा ने कहा कि हालांकि कुछ इलाकों में हर साल जलभराव होता है, लेकिन इस मौसम में हुई असाधारण रूप से भारी बारिश ने स्थिति को और खराब कर दिया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में शहरी बाढ़ की स्थिति ऊपरी असम में हुई तबाही के आगे फीकी पड़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर हम शिवसागर और चराइदेउ की बात करें तो गुवाहाटी की बात कोई नहीं करेगा। ऊपरी असम में स्थिति शहरी बाढ़ की तुलना में कहीं अधिक भयावह है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार की तत्काल प्राथमिकता राज्य भर में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत वितरण और पुनर्वास प्रदान करना है।

10 साल की सजा...

उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक रोकने के लिए पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो। इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया। वहीं यह भी एलान किया था कि पेपर लीक रोकने के लिए अगले हफ्ते संसद में नया बिल पेश किया जाएगा। इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने इससे पहले एलान किया था कि पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पेपर लीक से जुड़े मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे मामले का निपटारा करें और तीन महीने के भीतर सजा सुनाएं। नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही, शिक्षा प्रणाली में सुधार और मई में नीट-यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की जा रही है। पेपर लीक की मांगों के खिलाफ एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिन का अनशन किया था और संसद में भी हंगामा जारी है। इस मामले में सीबीआई की जांच जारी है। अब तक अलग-अलग राज्यों से 13 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। देश में पहले ही से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 लागू है। इसे 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू है। सरकार नए संशोधन कर कानून को और सख्त और प्रभावशाली करने की तैयारी में है। इस कानून के तहत अपराध गैर जमानती है और समझौता नहीं हो सकता। जांच डीएसपी रैंक या उससे सीनियर अफसर करेंगे।

सरकार के लिखित आश्वासन ...

के इस्तीफे पर कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। इस पर सोनम वांगचुक ने कहा कि यदि सरकार इस मांग पर फैसला नहीं करती है तो इसका नुकसान छात्रों का नहीं बल्कि स्वयं सरकार का होगा। सोनम वांगचुक ने नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के जंतर-मंतर स्थित आंदोलन के समर्थन में 28 जून को आमरण अनशन शुरू किया था। अनशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर पहले उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर उन्हें गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। वांगचुक ने देर रात जारी अपने वीडियो संदेश में बताया कि शुक्रवार तड़के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे। वीडियो में दोनों नेताओं ने पहले उन्हें सरकार का लिखित आश्वासन पढ़कर सुनाया फिर उन्हें तरल पदार्थ पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। आश्वासन पत्र में लिखा था कि सरकार नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों तथा 20 जुलाई को संसद मार्च में भाग लेने वाले लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं करने के प्रति सकारात्मक है। सरकार पहले ही यह आश्वासन दे चुकी है कि प्रश्नपत्र लीक की समस्या के समाधान और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए संसद में विस्तृत चर्चा कराई जाएगी। इसके अलावा, हालिया नीट प्रश्नपत्र लीक प्रकरण से जुड़े आत्महत्या पीड़ितों के परिजनों को उपयुक्त मुआवजा देने पर भी सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी। सोनम वांगचुक ने कहा कि पिछले दो दिनों से सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि केवल मौखिक भरोसे पर वह अनशन समाप्त नहीं करेंगे और उन्हें लिखित आश्वासन चाहिए। इसी कारण उन्हें दो दिन अतिरिक्त अनशन पर बैठना पड़ा। अंततः सरकार ने लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। वीडियो संदेश में वांगचुक ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद स्वयं उनसे मिलने पहुंचे या हस्ताक्षरयुक्त पत्र भेजकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। सांसदों ने आश्वस्त किया कि संसद में परीक्षा प्रणाली की विफलताओं, प्रश्नपत्र लीक और जवाबदेही तय करने पर विस्तार से चर्चा होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल नीट का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित कराना है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के सवाल पर सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार इस विषय पर उन्हें कोई आश्वासन नहीं दे सकी। उन्होंने कहा कि उनके सामने दो रास्ते थे या तो वह अनिश्चितकाल तक अनशन जारी रखते और संभवतः उसी में उनकी जान चली जाती या फिर छात्रों के व्यापक हितों को देखते हुए उन मुद्दों पर मिले लिखित आश्वासन को स्वीकार करते जिनका सीधा संबंध छात्रों के भविष्य से है। यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसका नुकसान छात्रों को नहीं बल्कि स्वयं सरकार को होगा। यदि सरकार समय रहते यह फैसला कर लेती तो उसका राजनीतिक नुकसान रुक सकता था। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा समय के साथ अपने आप तय हो जाएगा। सोनम वांगचुक ने कहा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना था कि आंदोलन में शामिल छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज न हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने लद्दाख में देखा है कि किस प्रकार वर्षों तक एफआईआर का बोझ युवाओं का भविष्य प्रभावित करता है। इसलिए छात्रों को कानूनी कार्रवाई से बचाने का लिखित आश्वासन उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने और संसद में जवाबदेही पर चर्चा कराने के आश्वासन को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत की संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और यदि वहां परीक्षा प्रणाली, शिक्षा सुधार तथा जवाबदेही पर गंभीर चर्चा होती है तो यह देश के छात्रों के हित में बड़ा कदम होगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों, अपने समर्थकों और आंदोलन से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त किया। अनशन समाप्त करने से पहले उन्होंने कहा कि 26 दिनों के बाद तरल पदार्थ का स्वाद उन्हें बेहद अच्छा लग रहा है, लेकिन *उनकी भूख समाप्त नहीं हुई है।* यह भूख जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की है तथा यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपने आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण रखें और किसी भी प्रकार की हिंसा अथवा असामाजिक तत्वों को आंदोलन का हिस्सा न बनने दें। अनशन समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि भूख का अंत... जवाबदेही की शुरुआत। सरकार और सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से मिले आश्वासन के बाद उन्होंने अनशन समाप्त किया है। संसद में परीक्षा प्रणाली की विफलताओं और जवाबदेही पर चर्चा होगी, नीट प्रश्नपत्र लीक से जुड़े आत्महत्या पीड़ित छात्रों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। इस बीच ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि सरकार जंतर-मंतर पर आंदोलनरत सीजेपी नेताओं के साथ संविधान क्लब में बातचीत कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं, सीजेपी नेतृत्व पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक उसका आंदोलन जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम वीडियो संदेश जारी कर प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई महीनों में सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।

एनटीए ने 47 ...

अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही सुधार के लिए और भी कदम उठाए जाएंगे। यह एनटीए में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा है।

असम बाढ़ : 11 जिलों की 7 लाख आबादी प्रभावित, छह और शव मिले

गुवाहाटी (हिंस)। असम में लगातार बरसात की वजह से बाढ़ के हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की ओर से जारी बीते 23 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 06 और लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस तरह राज्य में अब तक मरने वालों की कुल संख्या 47 हो गयी है। असम में खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली नदियों में बुढ़ीदिहिंग (चेनिमारी, खोवांग), दिसांग (नंगलामुराघाट), दिखौ (शिवसागर), धनसिरी (नुमालीगढ़), कुशियारा (श्रीभूमि) शामिल हैं। बीते गुरुवार रात हुई भारी बरसात के चलते गुवाहाटी के निचले इलाकों में भारी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। सड़कों पर भारी जल जमाव के चलते यातायात प्रभावित हुआ। जिसके चलते लोगों को अपने घर पहुंचने के लिए अलग-अलग इलाकों में जाम में देर तक फंसना पड़ा। जल जमाव का असर आज भी गुवाहाटी के विभिन्न हिस्सों में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा स्वयं बाढ़ से सबसे प्रभावित शिवसागर, चराईदेव एवं जोरहाट जिलों का बुधवार को दौरा करने के बाद गुरुवार को गोलाघाट एवं डिब्रूगढ़ जिलों में बनाए गए राहत शिविर एवं नुकसान वाले इलाकों का दौरा कर जायजा लिया। उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं, असम सरकार के मंत्री बिमल बोरा, केशव महंत, अजंता नेओग, अतुल बोरा एवं विधायक लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को राहत पहुंचाने के कार्य में जुटे हुए हैं। बाढ़ से वर्तमान समय में कुल 11 जिले प्रभावित हुए हैं। जिसमें गोलाघाट, होजई, कामरूप, चराइदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नगांव, कामरूप (मेट्रो), कार्बी आंग्लांग, तिनसुकिया शामिल हैं। बाढ़ से 11 जिलों के 37 राजस्व मंडलों के कुल 883 गांव प्रभावित है। राज्य की कुल 721024 आबादी एवं 25375.443 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए कुल 103 राहत शिविर एवं 255 राहत वितरण केंद्र समेत कुल 358 शिविर स्थापित किए गए हैं। राहत शिविरों में 24124 लोग आश्रय लिए हुए हैं। जबकि राहत वितरण केंद्रों पर 239864 गैर-शिविर निवासी राहत प्राप्त कर रहे हैं। बाढ़ के पानी से 23 जुलाई बरामद शवों की संख्या 06 दर्ज हुई। जिसमें चराईदेव में 02 और शिवसागर में 04 शव बरामद हुए। बाढ़ से प्रभावित जानवरों की कुल संख्या 371609 दर्ज हुई है। जिसमें बड़े 110393, छोटे 78107 एवं मुर्गी-पालन 183109 दर्ज हुए हैं। इस बीच बाढ़ के पानी में कुल 154 जानवर बह गये। जिसमें जोरहाट जिले में 23 एवं चराईदेव जिले में 131 पशु पानी में बह गए हैं। बाढ़ में राहत एवं बचाय अभियान में एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं (एफ एंड ईएस), सर्कल कार्यालय/स्थानीय प्रशासन, नागरिक सुरक्षा/प्रशिक्षित स्वयंसेवक और अग्निशमन विभाग जुटा हुआ है। वहीं आंशिक रूप से 8 कच्चे घरों को भी गुरुवार को नुकसान होने की जानकारी सामने आई है। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में राज्य सरकार ने कुल 173 मेडिकल टीमों को तैनात किया। इस दौरान 80 नावें भी राहत कार्य में जुटी रहीं। बाढ़ के पानी में फंसे 4455 लोगों को नावों द्वारा निकाला। वहीं 05 जानवरों को भी नावों के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित शिवसागर जिले में राहत के कार्य में 1 हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया। बाढ़ प्रभावितों के बीच राज्य सरकार की ओर से चावल (क्विंटल में)-2539.523, दाल (क्विंटल में)- 551.383, नमक (क्विंटल में)- 107.0165, मस्टर्ड ऑयल/सरसों का तेल (लीटर में)- 8620.92 साथ ही पशुओं का चारा-गेंहूं का चोकर (क्विंटल में)- 2089.57 और पशुओं का चारा-चावल का चोकर (क्विंटल में)- 41.02 राहत सामग्री बांटी गई। बाढ़ से बड़े पैमाने पर सड़क, पुल एवं अन्य आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर बजट सत्र में विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है।

गुवाहाटी में बाढ़ की स्थिति की मंत्री कौशिक राय ने की समीक्षा

गुवाहाटी (हिंस)। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौशिक राय ने शुक्रवार को जनता भवन के ब्लॉक-बी स्थित अपने कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में गुवाहाटी में मौजूदा बाढ़ की स्थिति और शहरी जलभराव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक में मंत्री ने गुवाहाटी नगर निगम (जीएमसी), लोक निर्माण विभाग (सड़क) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सहित सभी संबंधित एजेंसियों को शहर के सभी नालों, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित नालों की व्यापक सफाई और गाद हटाने का निर्देश दिया, ताकि वर्षा जल की निकासी सुचारु रहे और जलभराव की समस्या कम हो। कौशिक राय ने कामरूप (मेट्रो) के जिला आयुक्त को शहर की ड्रेनेज व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तथा वार्षिक रखरखाव कैलेंडर तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई को एक बार की प्रक्रिया नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि मानसून से पहले, मानसून के दौरान और बाद में नियमित रूप से तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक भारी वर्षा के बाद भी सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। मंत्री ने कहा कि शहरी बाढ़ की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय, समयबद्ध रखरखाव और जवाबदेही बेहद आवश्यक है। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार बेहतर समन्वय और सतत प्रयासों के माध्यम से गुवाहाटी को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और जलभराव से निपटने के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में आवास एवं शहरी कार्य विभाग की आयुक्त एवं सचिव कविता पद्मनाभन तथा कामरूप (मेट्रो) के जिला आयुक्त स्वप्निल पॉल वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इसके अलावा पीडब्ल्यूआरडी के आयुक्त एवं विशेष सचिव संजीब श्याम, विभाग के सचिव डॉ. जीवन बी, जीएमसी के आयुक्त चिन्मय फूकन, एनएचएआई के अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मेघालय भी गुवाहाटी की बाढ़ के लिए जिम्मेदार : प्रद्युत बरदलै

गुवाहाटी (हिंस)। दिसपुर के विधायक प्रद्युत बरदलै ने शुक्रवार को कहा कि गुवाहाटी में बार-बार आने वाली बाढ़ के लिए पड़ोसी राज्य मेघालय भी जिम्मेदार है। विधायक असम विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचने के दौरान सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही है और भारी बारिश के दौरान कृत्रिम बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। बरदलै ने कहा कि राज्य सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध कब्जों के कारण ही गुवाहाटी में कृत्रिम बाढ़ का स्वरूप लगातार भयावह होता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को असम में देर शाम से रात तक हुई मुसलाधार बरसात के चलते अधिकांश इलाकों में भारी जलजमाव की स्थित उत्पन्न हो गयी। जिसके चलते लोगों भारी मुसिबतों का सामना करना पड़ा। वाहनों को घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहना पड़ा।

विधायकों के लिए स्वास्थ्य योजनाओं पर जागरूकता बैठक आयोजित, जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील

गुवाहाटी (हिंस)। असम सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की पहल पर शुक्रवार को असम विधानसभा परिसर स्थित जीएनबी भवन सभागार में राज्य के विधायकों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को राज्य और केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं, रोग नियंत्रण कार्यक्रमों तथा जनस्वास्थ्य पहलों की विस्तृत जानकारी देना था। कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त-सचिव डॉ. पी अशोक बाबू के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) असम के मिशन निदेशक डॉ. लक्ष्मणन एस ने टीबी मुक्त भारत अभियान, स्कूल हेल्थ क्लब, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य मेगा कैंप, जापानी इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू तथा एड्स जागरूकता सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विधायकों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक प्रचार करने और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। मंत्री ने आयुष्मान भारत, स्नेह स्पर्श योजना, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपलब्ध विशेष स्वास्थ्य सेवाओं तथा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी भी साझा की। उन्होंने सभी विद्यालयों में प्रस्तावित हेल्थ क्लबों के सफल गठन में विधायकों के सहयोग की अपील की और स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति एवं चुनौतियों की समीक्षा के लिए प्रत्येक तीन माह में विधायकों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया। बैठक में असम विधानसभा के उपाध्यक्ष हाबे तेरोन, श्रम मंत्री रामेश्वर तेली, मत्स्य मंत्री नीलिमा देवी सहित कई विधायक उपस्थित रहे।

बाढ़ प्रभावित छात्रों और युवाओं के दस्तावेज दोबारा तैयार कराने में सहयोग करें : मंत्री बिमल बोरा

गुवाहाटी (हिंस)। असम के उद्योग, वाणिज्य एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री बिमल बोरा ने शिवसागर और चराईदेव जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित छात्रों और युवाओं के शैक्षणिक, पहचान एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को दोबारा तैयार कराने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के पदाधिकारियों को सक्रिय सहयोग करने का निर्देश दिया। शिवसागर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में मंत्री बोरा ने भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राकेश दास और राज्य समिति के पदाधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के समन्वय से प्रभावित छात्रों और युवाओं के आवश्यक दस्तावेजों की शीघ्र पुनर्प्राप्ति और पुनः तैयार कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने कहा कि आपदा की इस कठिन घड़ी में कोई भी छात्र या युवा केवल दस्तावेज नष्ट होने के कारण शिक्षा, रोजगार या अन्य आवश्यक कार्यों से वंचित न रहे।

बाढ़ को लेकर राजनीति करने के आरोप में अखिल गोगोई पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने साधा निशाना

गुवाहाटी (हिंस)। असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई पर सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के नेताओं ने भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्वाइंट आफ आर्डर के तहत आज बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष वाजेद अली चौधरी और कांग्रेस विधायक नुरुल हुदा ने बीते गुरुवार को असम विधानसभा में हुई घटना को *पूर्व नियोजित* बताते हुए कहा कि अखिल गोगोई बाढ़ जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। वाजेद अली चौधरी ने कहा कि सदन से बाहर निकलकर अखिल गोगोई ने कांग्रेस पर दोषारोपण किया, जिसको सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रसारित किया गया। वहीं संसदीय मंत्री पीयूष हजारिका ने भी अखिल के व्यवहार को असंसदीय करार करते हुए इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष रंजीत दास से कार्रवाई की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन के बाहर और सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणी को लेकर सदन में चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिल ने बीते कल सदन में दो मिनट बोलने की मुझसे अनुमति मांगी थी, मैंने समय दिया भी था, बावजूद अखिल ने टेबुल पर चढ़कर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि असम के संसदीय इतिहास में आज तक इस तरह की घटना कभी देखने को नहीं मिलती है। अध्यक्ष ने कहा कि सही अर्थों में गुरुवार के हंगामे की वीडियो फुटेज जारी कर राज्य की जनता को असली हकीकत बताना चाहिए। हालांकि उन्होंने वीडियो फुटेज जारी करने को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया। इस बीच सत्ता पक्ष के एक विधायक ने अखिल गोगोई के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की अध्यक्ष से मांग की। लेकिन अध्यक्ष ने कार्रवाई से इंकार किया। विधायकों ने शुक्रवार को असम विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने पहुंचने के दौरान सदन के बाहर भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिल गोगोई के आचरण को लेकर अपनी नाराजगी जताई। कांग्रेस विधायक जयप्रकाश दास ने कहा कि अखिल गोगोई को विधानसभा आने के बजाय अपने विधानसभा क्षेत्र शिवसागर में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में राजनीति करने के बजाय लोगों की सेवा करना अधिक जरूरी है। कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकदार ने भी अखिल गोगोई की आलोचना करते हुए कहा कि यदि वह (सिकदार) शिवसागर के विधायक होते तो इस समय विधानसभा नहीं आते। उन्होंने कहा कि यह राजनीति करने या लोगों को भ्रमित करने का समय नहीं है, बल्कि बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने का समय है। असम में बाढ़ को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने अखिल गोगोई पर आपदा को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है।

रुक्मिणीगांव में अब भी गंभीर बाढ़, सिविल डिफेंस की टीमें राहत कार्य में जुटीं

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी के विभिन्न हिस्सों के साथ ही रुक्मिणीगांव क्षेत्र में कृत्रिम बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। कई इलाकों में पानी सीने तक भरा हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सिविल डिफेंस के जवान लगातार अभियान चला रहे हैं। रबर की नावों के जरिए जलमग्न मोहल्लों में पहुंचकर जवान घर-घर जाकर फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गुवाहाटी में गुरुवार की देर शाम को हुई लगातार बरसात के चलते विभिन्न हिस्सों में भारी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी ।आज दूसरे दिन भी कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है।

गदाधर नदी में डूबने से एक किशोरी की मौत

धुबड़ी (हिंस/विभास)। धुबड़ी शहर के मेला घाट स्थित गदाधर नदी में शुक्रवार सुबह डूबने से 17 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। मृतका की पहचान अक्षरा गोवाला के रूप में हुई है। वह शिशुपाठशाला हायर सेकेंडरी स्कूल में हायर सेकेंडरी प्रथम वर्ष की छात्रा थी और स्थानीय व्यवसायी रामचंद्र गोवाला की पुत्री थी। परिजनों के अनुसार, घटना सुबह करीब 10 बजे की है। बताया गया कि अक्षरा वार्ड संख्या-1 स्थित अपने घर के समीप बहने वाली गदाधर नदी के किनारे गई थी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गई। देखते ही देखते वह तेज बहाव में डूब गई। घटना की सूचना मिलते ही उसके पिता के यहां कार्यरत कुछ लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और छात्रा की तलाश में नदी में उतर गए। बाद में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया।

कोकराझाड़ में श्रद्धा और उल्लास के साथ निकली भगवान जगन्नाथ की घर वापसी रथ यात्रा

कोकराझाड़ (विभास)। कोकराझाड़ जिले के फकीराग्राम में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की घर वापसी (बहुड़ा) रथ यात्रा पूरी श्रद्धा, उल्लास और भव्यता के साथ संपन्न हुई। फकीराग्राम के रेलवे कॉलोनी स्थित लोकनाथ बाबा मंदिर से रथ आयोजक समिति के तत्वावधान में आयोजित इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। दोपहर चार बजे शुरू हुई इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। पूरा क्षेत्र *जय जगन्नाथ* के उद्घोष से गूंज उठा और हर कोई भक्ति रस में सराबोर नजर आया। इस दौरान भक्तों में रथ की पवित्र रस्सी को खींचने के लिए होड़ मची रही। लोगों की अटूट मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने मात्र से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। फकीराग्राम बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए यह रथ यात्रा अपने निर्धारित पड़ाव से गुजरी। यात्रा सबसे पहले राधा-गोबिंदो मंदिर पहुंची, वहां से पुराणबाजार दुर्गा मंदिर होते हुए अंत में कुमारगंज में जाकर पूरी हुई। इस पावन अवसर पर स्थानीय निवासियों ने सेवा भाव का अनूठा उदाहरण पेश किया। चिलचिलाती और भीषण गर्मी के बीच यात्रा मार्ग पर जगह-जगह भक्तों के लिए शीतल जल, शरबत और पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसकी सभी ने भूरी-भरी प्रशंसा की। रथ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पूरे मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के शांतिपूर्ण ढंग से भगवान की एक झलक पा सकें और उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो सके।

राज्यपाल आचार्य ने 47वीं राज्य स्तरीय सीनियर एवं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का किया उद्घाटन

नलबाड़ी (हिंस)। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शुक्रवार को नलबाड़ी स्टेडियम, सरिहाथली में आयोजित 47वीं राज्य स्तरीय सीनियर एवं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से खेल संस्कृति को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन, सहनशक्ति और राष्ट्र निर्माण का सशक्त आधार हैं। असम एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से नलबाड़ी जिला प्रशासन और नलबाड़ी जिला खेल संघ के सहयोग से आयोजित इस चैंपियनशिप में राज्यभर से लगभग 1,200 एथलीट भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भागीदारी असम में विकसित हो रही खेल संस्कृति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक *विकसित भारत* के लक्ष्य को प्राप्त करने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं भविष्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करने का प्रभावी मंच प्रदान करती हैं। राज्यपाल ने कहा कि असम की धरती ने देश को अनेक उत्कृष्ट खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष, परिश्रम और समर्पण से राज्य और राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने एथलेटिक्स के दिग्गज भोगेश्वर बरुवा, हिमा दास, अमलान बोरगोहाईं और मौमिता मंडल, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाईं और शिवा थापा तथा तीरंदाज जयंत तालुकदार का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। आचार्य ने कहा कि एथलेटिक्स खिलाड़ियों में सहनशक्ति, आत्म-अनुशासन, धैर्य और प्रतिबद्धता जैसे गुण विकसित करता है, जो किसी भी खिलाड़ी की सफलता की मजबूत नींव होते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से खेल भावना, निष्पक्षता और ईमानदारी के उच्चतम मानकों का पालन करने का आग्रह करते हुए कहा कि पदक सफलता का प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन अनुशासन और दृढ़ संकल्प ही एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करते हैं। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की खेल संबंधी पहल *खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट* और *टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस)* का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने देश के खेल परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की भी सराहना करते हुए कहा कि उनकी पहल पर असम में विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना विकसित की जा रही है और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले अनेक खिलाड़ी भविष्य में असम और भारत का गौरव बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि खेलों में किया गया निवेश वास्तव में देश के भविष्य में निवेश है, जो स्वस्थ, आत्मविश्वासी और सशक्त युवा पीढ़ी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में असम सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्जीत दैमारी, वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुवा, विधायक ऋतुबरन शर्मा, नलबाड़ी के आयुक्त निबेदन दास पटवारी, नलबाड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बिबेकानंद दास सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

संपादकीय

जिनेवा संधियों के खिलाफ जंग

आज ईरान युद्ध ऐसी पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, जहां 1949 की जिनेवा अंतरराष्ट्रीय सन्धियों का उल्लेख अनिवार्य है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के आईआरजीसी ने तो उन सन्धियों के प्रति आंखें मूंद ली हैं, अब यह हकीकत लगता है। विध्वंस, विस्फोट और अंततः विनाश जारी है, जिनमें मानवाधिकार और मानवीय व्यवस्थाएं भी कुचली जा रही हैं। कोई वैश्विक संस्थान अथवा मंच या राष्ट्र-समूह नहीं है, जो इन पागल, बौखलाए और संहारी जंगियों को समझा सके या रोक लगा सके। हमें एक बार फिर लिखना-कहना पड़ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अब एक लुंज-पुंज संस्थान बन कर रह गया है। अब यह भाषण पेलने का ही मंच रह गया है, लिहाजा उस पर ढक्कन बंद कर देना चाहिए। युद्ध के अलावा, अब यह संस्थान विस्थापन, शरण, भोजन, पानी, स्वास्थ्य, संरक्षण और जलवायु-परिवर्तन तक किसी भी लिहाज से सशक्त मंच नहीं रहा है, क्योंकि अब कोई भी देश उसकी अपील या आह्वान की परवाह तक नहीं करता। वीटो वाले देशों के अपने गिरोह, षड्यंत्र और कूटनीतिक हित हैं। अब विश्व के असंख्य करदाताओं के अरबों डॉलर (या रुपए) फूंकना बेमानी है। बहरहाल जिनेवा सन्धि के अनुच्छेद 52 में स्पष्ट प्रावधान है कि युद्ध के दौरान नागरिकों, स्कूलों, अस्पतालों, नागरिक व्यवस्थाओं पर हमले नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 54 में उल्लेख है कि पानी, खाद्य और अन्य नागरिक सुविधाओं पर हमला करना या उन्हें नष्ट करना प्रतिबंधित है। यह चेतावनी भी जोड़ी गई है कि यदि नागरिकों की जान का खतरा है, तो इन सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर हमले पूरी तरह निषिद्ध हैं। ये चार सन्धियां खुद दुनिया के बड़े देशों ने, आपसी विमर्श के बाद, पारित की थीं, हस्ताक्षर किए थे, लेकिन युद्ध कोई भी हो, इन सन्धियों की धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं। मौजूदा ईरान युद्ध हो अथवा साढ़े चार साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध हो, ये सन्धियां चीत्कार करती रही हैं। ऐसा आभास होता है मानो जिनेवा सन्धियों के खिलाफ ही जंग जारी है! अमरीका ने तो ईरान युद्ध की शुरुआत में ही एक स्कूल पर हमला कर 168 बच्चियों का सामूहिक नरसंहार कर दिया था। अमरीका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई दंडात्मक फैसला नहीं, महज बयान से क्या होता है? अमरीकी लड़ाकू विमान बीती 11 रातों से ईरान पर लगातार मिसाइल हमले, बमबारी कर रहे हैं, हमले होर्मुज तट से राजधानी तेहरान तक विनाश की कहानियां लिख रहे हैं, त्रासदियां कितनी हुईं, फिलहाल इनका कोई डाटा सामने नहीं है। नुकसान अकल्पनीय है। हमले बिजलीघरों, पानी के संयंत्रों, पुलों, इमारतों, परमाणु स्थलों के करीब किए जा रहे हैं, लेकिन विश्व में जिनेवा सन्धियों को लेकर कोई हस्तक्षेप या बयान सामने नहीं आया है। दुनिया के सबसे बड़े गुंडे के खिलाफ बोलने की हिमाकत कौन कर सकता है? ईरान में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की जानकारी के लिए, एक सर्वेक्षण किया गया। उसमें 45 फीसदी लोग युद्ध के कारण खौफजदा सामने आए, करीब 49 फीसदी ने युद्ध बढ़ने का डर जताया, 44.3 फीसदी ने युद्धविराम की इच्छा जताई, 81 फीसदी से अधिक ऐसे थे, जिन तक बुनियादी सुविधाओं और सामान की पहुंच नहीं थी, करीब 63 फीसदी लोगों में युद्ध के कारण गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ा है और 50 फीसदी से अधिक लोगों में किसी बेहतर सुधार की उम्मीद नजर नहीं आई। साफ है कि ईरान युद्ध में जिनेवा सन्धियां चीत्कार रही हैं। लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। काम-धंधे छिन रहे हैं, बेरोजगारी के साथ भुखमरी भी बढ़ रही है। अमरीका भी यही चाहता है कि ईरान का अवाम मौजूदा हुकूमत के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए। यही अमरीका की असल सामरिक कामयाबी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश हैं कि ईरान में 'नरक' के दरवाजे खोल दिए जाएं। एक साथ 17 शहरों और 95 ठिकानों पर अमरीकी हमले किए गए हैं। पलटवार में ईरान ने जॉर्डन को विनाशक हमलों का 'एपिसेंटर' बना दिया है। जॉर्डन के साथ-साथ बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सीरिया में भी हमलों ने तबाही मचा रखी है। अमरीकी सैनिक भी मारे गए हैं, जबकि 400 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। अमरीका के 9.91 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।

अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के आईआरजीसी ने तो उन सन्धियों के प्रति आंखें मूंद ली हैं, अब यह हकीकत लगता है। विध्वंस, विस्फोट और अंततः विनाश जारी है, जिनमें मानवाधिकार और मानवीय व्यवस्थाएं भी कुचली जा रही हैं। कोई वैश्विक संस्थान अथवा मंच या राष्ट्र-समूह नहीं है, जो इन पागल, बौखलाए और संहारी जंगियों को समझा सके या रोक लगा सकें। हमें एक बार फिर लिखना-कहना पड़ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अब एक लुंज-पुंज संस्थान बन कर रह गया है। अब यह भाषण पेलने का ही मंच रह गया है, लिहाजा उस पर ढक्कन बंद कर देना चाहिए। युद्ध के अलावा, अब यह संस्थान विस्थापन, शरण, भोजन, पानी, स्वास्थ्य, संरक्षण और जलवायु-परिवर्तन तक किसी भी लिहाज से सशक्त मंच नहीं रहा है, क्योंकि अब कोई भी देश उसकी अपील या आह्वान की परवाह तक नहीं करता। वीटो वाले देशों के अपने गिरोह, षड्यंत्र और कूटनीतिक हित हैं। अब विश्व के असंख्य करदाताओं के अरबों डॉलर (या रुपए) फूंकना बेमानी है। बहरहाल जिनेवा सन्धि के अनुच्छेद 52 में स्पष्ट प्रावधान है कि युद्ध के दौरान नागरिकों, स्कूलों, अस्पतालों, नागरिक व्यवस्थाओं पर हमले नहीं किए जाएंगे।

कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि हजारों चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा की

डॉक्टर बनने की राह में संवेदनाएँ कहाँ खो जाती हैं?

देश में जब भी नीट (NEET) परीक्षा होती है, उसके बाद केवल परिणामों की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की चर्चा शुरू हो जाती है। कभी पेपर लीक, कभी परीक्षा की पारदर्शिता, कभी आरक्षण, कभी कट-ऑफ और कभी लाखों विद्यार्थियों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव को लेकर बहस छिड़ जाती है। हर वर्ष करोड़ों सपनों का भार इस एक परीक्षा पर टिका होता है। माता-पिता अपनी वर्षों की बचत दाँव पर लगा देते हैं, विद्यार्थी दिन-रात एक कर देते हैं और समाज उन सफल अभ्यर्थियों को भविष्य का जीवनरक्षक मानकर गर्व महसूस करता है। लेकिन इन तमाम बहसों के बीच एक ऐसा प्रश्न है, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, फिर भी सबसे कम पूछा जाता है। आखिर यही बच्चे, जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश करते हैं, उनमें से कुछ आगे चलकर ऐसे डॉक्टर क्यों बन जाते हैं जिनके व्यवहार को लेकर समाज में असंतोष दिखाई देता है? क्यों कभी-कभी मरीज को लगता है कि उसके सामने बैठा व्यक्ति पहले डॉक्टर नहीं, बल्कि एक व्यवसायी है? यह प्रश्न किसी पूरे चिकित्सक समुदाय पर आरोप नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की पड़ताल है जो एक संवेदनशील विद्यार्थी को कभी-कभी संवेदनहीन पेशेवर में बदल देती है। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि देश के अधिकांश डॉक्टर आज भी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और करुणा के साथ अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि हजारों चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा की। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संसाधनों के बीच कार्य करने वाले डॉक्टर आज भी चिकित्सा सेवा की गरिमा बनाए हुए हैं। इसलिए कुछ लोगों की गलतियों के आधार पर पूरे चिकित्सक समुदाय का मूल्यांकन करना अन्याय होगा। लेकिन यदि समाज में डॉक्टरों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है, तो उसके कारणों पर गंभीरता से विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। समस्या की शुरुआत मेडिकल कॉलेज से भी पहले हो जाती है। आज डॉक्टर बनने की तैयारी एक प्रतियोगी उद्योग बन चुकी है। कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को सफलता का अर्थ केवल रैंक, अंक और सीट समझाया जाता है। चिकित्सा को सेवा नहीं, बल्कि उपलब्धि और प्रतिष्ठा का माध्यम मानने की मानसिकता धीरे-धीरे विकसित होने लगती है। जब लक्ष्य केवल किसी भी कीमत पर मेडिकल सीट प्राप्त करना रह जाए, तब संवेदनशीलता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों की चर्चा पीछे छूट जाती है। इसके बाद यदि कोई छात्र अत्यधिक महँगे निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेता है, जहाँ शिक्षा पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये तक खर्च होते हैं, तो आर्थिक दबाव भी उसके भविष्य को प्रभावित करता है। कई परिवार कर्ज लेकर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह भावना जन्म लेती है कि अब इस निवेश की भरपाई करनी है। यह सोच चिकित्सा की मूल भावना के विपरीत है, लेकिन शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण ने इस मानसिकता को कहीं न कहीं जन्म दिया है। मेडिकल शिक्षा स्वयं भी अत्यंत कठिन है। वर्षों तक लगातार अध्ययन, इंटर्नशिप की लंबी ड्यूटी, रातभर जागकर काम करना, गंभीर मरीजों से रोज सामना होना, मानसिक तनाव और कई बार कठोर प्रशिक्षण—यह सब एक युवा छात्र के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यदि इस दौरान उसे भावनात्मक सहयोग, नैतिक चिकित्सा और मानवीय व्यवहार का पर्याप्त प्रशिक्षण न मिले, तो धीरे-धीरे मरीज एक इंसान नहीं, बल्कि एक ₹केस₹ बनकर रह जाता है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। एक-एक डॉक्टर को सैकड़ों मरीज देखने पड़ते हैं। सीमित संसाधनों, दवाओं की कमी और प्रशासनिक दबाव के बीच हर मरीज को पर्याप्त समय देना कई बार संभव नहीं होता। दूसरी ओर निजी अस्पतालों में कई स्थानों पर आय, पैकेज और लक्ष्य आधारित कार्य संस्कृति का दबाव रहता है। ऐसे माहौल में चिकित्सा सेवा और व्यापार के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। समस्या केवल डॉक्टरों की भी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा ढाँचा कई बार ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करता है जहाँ मानवीय संवेदनाएँ धीरे-धीरे थकने लगती हैं। लगातार तनाव, मुकदमों का डर, हिंसा की घटनाएँ, सोशल मीडिया पर बिना तथ्य के आरोप और हर परिस्थिति में चमत्कार की अपेक्षा—ये सभी बातें डॉक्टरों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव डालती हैं। जब समाज और व्यवस्था दोनों किसी पेशे को लगातार तनाव में रखें, तो उसका असर व्यवहार पर पड़ना स्वाभाविक है। इसके बावजूद यह स्वीकार करना होगा कि कुछ डॉक्टरों द्वारा अनावश्यक जाँचें लिखना, कमीशन आधारित रेफरल देना, अत्यधिक शुल्क लेना या मरीज के साथ असम्मानजनक व्यवहार करना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। चिकित्सा केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि विश्वास का भी पेशा है। एक बार यदि यह विश्वास टूटता है तो उसकी भरपाई अत्यंत कठिन होती है। सबसे बड़ी कमी शायद हमारी चिकित्सा शिक्षा में नैतिक प्रशिक्षण की है। मेडिकल विद्यार्थियों को शरीर की संरचना, रोगों की पहचान और आधुनिक उपचार पद्धतियाँ तो विस्तार से पढ़ाई जाती हैं, लेकिन करुणा, संवाद, सहानुभूति और चिकित्सा नैतिकता को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती, जितनी मिलनी चाहिए। जबकि मरीज को सबसे पहले दवा नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। कई बार डॉक्टर का एक मधुर शब्द भी उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। नीट पर होने वाली बहस केवल परीक्षा की निष्पक्षता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि हमें वास्तव में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए तो मेडिकल शिक्षा को केवल ज्ञान और तकनीक तक सीमित रखने के बजाय उसे मानवीय मूल्यों से भी जोड़ना होगा। मेडिकल कॉलेजों में नैतिक शिक्षा, सामुदायिक सेवा, ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर, संवाद कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को यह समझाना होगा कि चिकित्सा केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी है। सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, निजी मेडिकल शिक्षा की फीस को अधिक न्यायसंगत बनाने, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। जब व्यवस्था ही संतुलित होगी, तभी उससे निकलने वाले पेशेवर भी अधिक संतुलित होंगे। समाज को भी आत्ममंथन करना चाहिए। डॉक्टर से चमत्कार की अपेक्षा करना, छोटी-सी असफलता पर हिंसा करना या बिना तथ्यों के पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। डॉक्टर और मरीज का संबंध विश्वास पर आधारित होता है और इस विश्वास की रक्षा दोनों पक्षों को मिलकर करनी होगी। नीट की निष्पक्षता आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक यह सुनिश्चित करना है कि मेडिकल कॉलेज से निकलने वाला प्रत्येक डॉक्टर केवल सफल परीक्षार्थी न हो, बल्कि संवेदनशील इंसान भी हो। देश को ऐसे चिकित्सकों की आवश्यकता है जिनके हाथों में विज्ञान की दक्षता हो, मस्तिष्क में ज्ञान हो और हृदय में करुणा। क्योंकि चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सबसे पवित्र सेवाओं में से एक है। नीट के विवादों के बीच यदि हम इस बड़े प्रश्न पर भी गंभीरता से विचार कर सकें कि डॉक्टर बनने की यात्रा में संवेदनाएँ क्यों कमजोर पड़ जाती हैं, तो शायद भविष्य में हमें केवल उत्कृष्ट चिकित्सक ही नहीं, बल्कि ऐसे डॉक्टर भी मिलेंगे जिन पर मरीज बिना किसी भय और संदेह के अपना जीवन सौंप सकें। किसी भी राष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था की असली पहचान उसकी मशीनों, भवनों या तकनीक से नहीं, बल्कि डॉक्टर और मरीज के बीच मौजूद विश्वास से होती है। उस विश्वास को बचाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

माता-पिता अपनी वर्षों की बचत दाँव पर लगा देते हैं, विद्यार्थी दिन-रात एक कर देते हैं और समाज उन सफल अभ्यर्थियों को भविष्य का जीवनरक्षक मानकर गर्व महसूस करता है। लेकिन इन तमाम बहसों के बीच एक ऐसा प्रश्न है, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, फिर भी सबसे कम पूछा जाता है। आखिर यही बच्चे, जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश करते हैं, उनमें से कुछ आगे चलकर ऐसे डॉक्टर क्यों बन जाते हैं जिनके व्यवहार को लेकर समाज में असंतोष दिखाई देता है? क्यों कभी-कभी मरीज को लगता है कि उसके सामने बैठा व्यक्ति पहले डॉक्टर नहीं, बल्कि एक व्यवसायी है? यह प्रश्न किसी पूरे चिकित्सक समुदाय पर आरोप नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की पड़ताल है जो एक संवेदनशील विद्यार्थी को कभी-कभी संवेदनहीन पेशेवर में बदल देती है। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि देश के अधिकांश डॉक्टर आज भी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और करुणा के साथ अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

देश | दुनीया से

नीट विवाद पर क्यों थम गईं संसद : छात्रों में असंतोष या विपक्ष का सियासी दांव?

युवाओं में गहराता अविश्वास सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। बार-बार लीक होते पेपरों और प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी से देश के मध्यमवगाय और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं का भरोसा भारत की चयन और परीक्षा प्रणालियों से डगमगा रहा है। यह अविश्वास देश के जनसांख्यिकी लाभांश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। संसद के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्र की सर्वोच्च पंचायत संसद केवल विधायी बहसों या नीतिगत बहसों का केंद्र नहीं रही, बल्कि यह देश के लाखों युवाओं के भविष्य, आक्रोश और असंतोष का रणक्षेत्र बन गई है। संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही व्यवधान उत्पन्न होता नजर आ रहा है। विपक्षी दलों के सांसदों के इस मामले को लेकर कड़े तेवर हैं और सरकार के खिलाफ अलग अलग रुप में आंदोलन चलाने पर उतारु हैं यानी पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस पूरे बवाल के मूल में नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) परीक्षा में कथित धांधली, पेपर लीक के आरोप, और राजधानी दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों तथा युवाओं पर पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग है। विपक्ष अब सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीपे की मांग पर अड़ गया है। सड़कों पर शुरू हुआ एक शैक्षणिक आंदोलन अब देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है, जिसने संसद में सरकार के विधायी एजेंडे पर गंभीर दबाव बना दिया है। भारत जैसे जीवंत और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब देश का युवा सड़कों पर उतर आए और संसद की कार्यवाही ठप हो जाए, तो यह पूरी व्यवस्था के लिए चिंतन का विषय है। संसद का काम केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि देश के नागरिकों, विशेषकर युवाओं के संशय और पीड़ा का समाधान करना भी है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह विपक्ष और प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक पारदशा संवाद कायम करे, ताकि जांच पर विश्वास बहाल हो सके। वहीं, विपक्ष को भी चाहिए कि वह विधायी कामकाज में भागीदारी करते हुए संसद को

ही अपनी बात और तर्कों का सबसे मजबूत मंच बनाए। यदि समय रहते इस गतिरोध और युवा असंतोष को तरकिक परिणति तक नहीं पहुंचाया गया, तो इसका नुकसान केवल राजनीति को नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य उसके युवाओं को भुगतना पड़ेगा। सड़कों से संसद तक विपक्ष का एकीवृत एजेंडा - विपक्ष को नीट और छात्र असंतोष के रूप में एक ऐसा सर्वव्यापी मुद्दा मिल गया है जो सीधे देश के हर दूसरे-तीसरे परिवार को प्रभावित करता है। विपक्षी दल इसे आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भी एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में विकसित कर रहे हैं। संसद के भीतर और बाहर विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, वामपंथी दलों, तृणमूल कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शायद विपक्ष का सबसे बड़ा हमला केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि जब देश की सबसे बड़ी और संवेदनशील चिकित्सा प्रवेश परीक्षा की साख तार-तार हो गई है, तो मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। विपक्ष का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री पद पर बने रहेंगे, तब तक किसी भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहेंगे। कांग्रेस सांसदों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के मेधावी छात्रों की आवाज सुनने के बजाय पुलिस की लाठियों से उसे दबाना चाहती है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक तरफ तो चर्चा की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार इसके लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष संसद के भीतर हंगामा व नारेबाजी करके कार्यवाही को चलने नहीं दे रहे हैं। शायद विपक्षी दल इस मुद्दे पर अपनी सियासी रणनीति को मजबूत करना चाहता है। विपक्ष का दावा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है और इसके शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय किए बिना केवल छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराना अन्याय है। सरकार का दावाः सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार - संसद और सड़को पर विपक्ष के लगातार जारी आक्रामक तेवरों और हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने भी अपना रुख साफ किया है। सरकार का कहना है कि वह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बारबार सदन में दोहराया कि सरकार नियम के तहत नीट मामले समेत किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर प्रश्नकाल के बाद विस्तृत चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष चर्चा करने के बजाय केवल सदन को ठप करने की राजनीति कर रहा है। सरकार का तर्क है कि पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए नया और कठोर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम लागू किया जा चुका है। उच्च स्तरीय जांच एजेंसियां हर पहलू की गहनता से पड़ताल कर रही हैं। सरकार का कहना है कि बिना ठोस तथ्यों के पूरी परीक्षा को अचानक रद्द कर देना या जल्दबाजी में कोई पैसला लेना उन लाखों ईमानदार और मेधावी छात्रों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने वर्षो तक दिन-रात मेहनत की है। देश में एक बड़ा सामाजिक व राजनीतिक मोड़ - नीट विवाद और जंतर-मंतर पर हुईं पुलिस कार्रवाई के बाद देश के माहौल में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है।

आप का | नजरीया

पीएम आवास तक तकरार

पेपरलीक आंदोलन, तकरार और विरोध-प्रदर्शन प्रधानमंत्री आवास की दहलीज तक पहुंच गया। यकीनन यह चौंकाने वाला यथार्थ है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ स्वीकार नहीं है। यह दंडनीय अपराध है। राजधानी दिल्ली में आंदोलन के स्थान चिह्नित हैं। पेपरलीक और युवाओं के भविष्य पर कोई तकरार है, तो उसके लिए संसद का मंच है। कमोबेश संसद में विपक्ष हंगामा करने, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी से बाज आएगा, तो सदन में इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। यह आश्वासन प्रधानमंत्री मोदी तक ने दिया है और एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए भी आश्वस्त किया है कि पेपरलीक के 'माफिया' को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। आरोपित जेल में भी हैं। संसद सत्र जारी है, लेकिन कार्यवाही बंजर है, क्योंकि विपक्ष को हंगामा करना ही विशेषाधिकार लगता है। बहरहाल संसद के दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष-राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे-ने स्थापित कानून को तोड़ा है। खड़गे का सरकारी आवास 10, राजाजी मार्ग है, जो प्रधानमंत्री आवास से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। 21 जुलाई को खड़गे का 84वां जन्मदिन था, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के अलावा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और अन्य महत्वपूर्ण चेहरे खड़गे के आवास पर जुटे थे। संभवतः वहीं रणनीति तय हुई और कांग्रेसी पैदल चल कर ही प्रधानमंत्री आवास की दहलीज तक पहुंच गए। दलील दी गई कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं, लिहाजा हम उनसे मिलने आए हैं। यह कुतर्क के अलावा कुछ भी नहीं। यह धरना सुरक्षा-व्यवस्था का घोर उल्लंघन था। चूंकि अधिकतर सांसद थे, लिहाजा वे संसद भवन में ही निश्चित स्थान पर धरना और नारेबाजी कर सकते थे। प्रधानमंत्री आवास की वह दहलीज 'उच्चतम सुरक्षा' क्षेत्र है, लिहाजा 'अति संवेदनशील' भी है। वहां से प्रधानमंत्री का काफिला ही आ-जा सकता है। वीवीआईपी मेहमान भी उसी रास्ते से प्रधानमंत्री से मुलाकात करने आते हैं। सवाल है कि क्या पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इस धरने की भनक तक नहीं लगी? प्रधानमंत्री को पल-पल की खबर दी जाती है, फिर इतनी चूक कैसे हो गई? बहरहाल आजादी के बाद सिर्फ दो बार प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनबाजी की गई है, लेकिन दोनों बार 'नेता प्रतिपक्ष' शामिल नहीं थे। 1999 में आईसी-814 विमान अपहरण के वक्त पीड़ित, चिंतित जनता प्रधानमंत्री आवास तक पहुंची थी, क्योंकि विमान में कई यात्री सवार थे और अपहरण आतंकियों ने किया था। तब देश के प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी थे। दूसरी बार, 2012 में अन्ना हजारे आंदोलन के समय युवाओं की भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया था। डॉ. मनमोहन सिंह तब देश के प्रधानमंत्री थे। दरअसल किसी भी विवाद, मुद्दे, समस्या, आपदा, कांड का न्यायिक निपटारा प्रधानमंत्री आवास पर धरना देकर हासिल नहीं किया जा सकता। मौजूदा कांग्रेसी धरना राजनीतिक अराजकता, मेरी मर्जी वाला अहंकार और पेपरलीक पर विभाजित राजनीति का स्पष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री दफ्तर में राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन दो बार धरनास्थल तक आए और राहुल गांधी से संवाद किया, उन्हें प्रधानमंत्री आवास की दहलीज की संवेदनशीलता समझाई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं माने। अपनी बात से मुकरते रहे और कई बार जवाब दिया-'मेरी मर्जी..!' देश किसी व्यक्ति की मनमर्जियों से नहीं चला करता। अंततः पुलिस के जवानों ने हल्का बलप्रयोग करते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को टांगते हुए उठाया, हिरासत में लिया और बस में ठेल कर छत्रसाल स्टेडियम ले गए। देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया। प्रियंका गांधी को भी जबरन उठा कर बस में बिठाया गया। मंदिर मार्ग थाने में उनसे मिलने मां सोनिया गांधी गईं। उन्हें भी रिहा कर दिया गया। दरअसल कांग्रेस सोच रही है कि पेपरलीक पर मोदी सरकार बैकफुट पर है। यह व्यापक वोट बैंक का भी मुद्दा है, लिहाजा राहुल गांधी 'गूंज' नाम से एक अभियान छात्रों के लिए चला रहे हैं।

पेपरलीक और युवाओं के भविष्य पर कोई तकरार है, तो उसके लिए संसद का मंच है। कमोबेश संसद में विपक्ष हंगामा करने, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी से बाज आएगा, तो सदन में इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। यह आश्वासन प्रधानमंत्री मोदी तक ने दिया है और एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए भी आश्वस्त किया है कि पेपरलीक के 'माफिया' को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। आरोपित जेल में भी हैं। संसद सत्र जारी है, लेकिन कार्यवाही बंजर है, क्योंकि विपक्ष को हंगामा करना ही विशेषाधिकार लगता है। बहरहाल संसद के दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष-राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे-ने स्थापित कानून को तोड़ा है। खड़गे का सरकारी आवास 10, राजाजी मार्ग है, जो प्रधानमंत्री आवास से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। 21 जुलाई को खड़गे का 84वां जन्मदिन था, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के अलावा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और अन्य महत्वपूर्ण चेहरे खड़गे के आवास पर जुटे थे। संभवतः वहीं रणनीति तय हुई और कांग्रेसी पैदल चल कर ही प्रधानमंत्री आवास की दहलीज तक पहुंच गए। दलील दी गई कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं, लिहाजा हम उनसे मिलने आए हैं।

कुछ | अलग

हल्ला मचाओ!

हल्ला मचाने वाले के बेर बिकते हैं। चीख जितनी तीखी होगी, असर उतना ही पुरजोर से होगा। वैसे भी जिधर देखो उधर शोर हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण से न संसद बच पा रही और न राज्यों की विधानसभाएं। हल्ला मचाकर बात मनवाना हमारी नई कल्चर है। जो लोग चीख नहीं पाते, वे कमजोर और दब्बू हैं। हमारे राजनेता इस मामले में सबसे अग्रणी हैं। सारे ऐब व दोषी पाए जाने के बाद में भी इतना चीखते हैं कि उनके अपराध गंगाजल की तरह पवित्र हो जाते हैं। वे बेवकूफ थोड़े ही हैं, जो बेकार में चीखेंगे। हल्ला मचाकर वे किसी सरकार को गिरा सकते हैं अथवा अपनी बेसुरी चिल्ल-पों से किसी का इस्तीफा झटक लेते हैं। किसी की जांच करवानी हो तो हल्ला मचाओ, किसी विधेयक को पास नहीं करवाना हो तो हल्ला मचाओ, तिल का ताड़ बनाना हो तो हल्ला मचाओ, उनकी मनचाही न हो तो हल्ला मचाओ, संसद या विधानसभा की कार्यवाही ठप्प करनी हो तो हल्ला मचाओ, सत्तापक्ष को नहीं सुनना हो तो हल्ला मचाओ और खुद पर आंच गिर रही हो तो हल्ला मचाओ। कुल मिलाकर काम न तो करो न करने दो और खामख्वाह हल्ला मचाओ। चुनाव में जीत जाओ तो हल्ला मचाओ और हार जाओ तो हल्ला मचाओ। सरकार को एक काम करते एक महीना हो जाए तो हल्ला मचाओ, सरकार की विफलताओं को लेकर हल्ला मचाओ। उलटा-सीधा बयान मुंह से निकल जाए तो हल्ला मचाओ, महिला आरक्षण विधेयक में कमी हो तो हल्ला मचाओए गरीबों के लिए कोई योजना शुरू करो तो हल्ला मचाओ, अच्छा बजट बना हो तो हल्ला मचाओ, मंत्री नहीं बनाओ तो हल्ला मचाओ, मुख्यमंत्री बनते-बनते रह जाओ तो हल्ला मचाओ, मनपसंद जांच आयोग न हो तो हला मचाओ और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक हल्ला मचाओ।

दृष्टि | कोण

प्रदेश के स्कूलों में फिटनेस के लिए समय कब?

हिमाचल के डेढ़ सौ स्कूल सीबीएसई से संबद्धता तो ले चुके हैं, देर बाद ही सही स्टाफ भी मिल जाएगा, मगर क्या अब भी ड्रिल के पीरियड में खेल मैदान में व्यायाम व खेल न होकर कक्षा के कमरे में नैतिक शिक्षा पढ़ाकर खानापूर्ति की जाएगी? वर्षों से स्कूली स्तर पर फिटनेस कार्यक्रम शुरू करने की बात इस कॉलम के माध्यम से हो रही है तथा हमने भी व्यक्तिगत तौर पर प्रदेश के बड़े निजी स्कूलों के प्रबंधकों से भी कई बार बात की है, मगर हिमाचल प्रदेश का कोई भी सरकारी या निजी स्कूल अपने यहां फिटनेस कार्यक्रम लागू करने में सफल नहीं रहा है। कई बार नए शिक्षा सत्र शुरू होकर खत्म हो गए, मगर फिटनेस कार्यक्रम कहीं भी शुरू नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विद्यालयों में विद्यार्थियों की सामान्य फिटनेस के लिए पहले की तरह अनिवार्य रूप से ड्रिल के पीरियड का प्रावधान किया है, मगर राज्य में फिटनेस संस्कृति के अभाव में धरातल पर कुछ भी सकारात्मक नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग के स्कूलों में अब मैदान की जगह कक्षा के कमरे में खेल व व्यायाम की जगह नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा का मतलब शरीर व मन दोनों का विकास करना है, तो शिक्षण विषयों के रिपोर्ट कार्ड की तरह स्वास्थ्य के मानकों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रत्येक विद्यार्थी का हर स्कूल में अनिवार्य रूप से हो। क्योंकि भाषा व अन्य शिक्षण विषयों की तरह ही स्वास्थ्य के मूल स्तंभ स्पीड, सट्रेंथ, इडोरेंस व लचक आदि का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी उसी उम्र में शुरू करना होता है। शिक्षण विषयों के लिए तो स्कूलों के पास शिक्षक सहित पूरा प्रबंध है, मगर स्वास्थ्य के घटकों को विकसित करके उनका मूल्यांकन करने की कोई भी सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस विषय पर स्कूलों व अभिभावकों को कई बार चेताया जा चुका है, मगर कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी देश को इतनी क्षति युद्ध या महामारी से नहीं होती है जितनी तबाही नशे के कारण हो सकती है। आज जब देश के अन्य राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में भी नशा युवा वर्ग पर ही नहीं किशोरों तक चरस, अफीम,

स्मैक, नशीली दवाओं तथा दूरसंचार के माध्यमों के दुरुपयोग से शिकंजा कस रहा है, इसलिए सरकार, स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों को इस विषय पर जरूरी कदम जल्दी ही उठा लेने चाहिएं। यदि विद्यार्थी किशोरावस्था में नशे से बच जाता है तो वह फिर युवावस्था आते आते समझदार हो गया होता है। माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विधाओं में व्यस्त रखने के साथ-साथ शारीरिक फिटनेस की तरफ मोडना बेहद जरूरी हो जाता है। मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा के बिना अधूरा है। शिक्षा की परिभाषा में साफ-साफ लिखा है कि यहां शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से बराबर विद्यार्थियों का विकास करना है जिससे वे आगे चलकर जीवन को सफलतापूर्वक खुशहाल जी सकें। शारीरिक विकास के लिए खेलों के माध्यम से फिटनेस कार्यक्रम बहुत जरूरी हो जाता है। खेल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी को नशे से दूर रखा जा सकता है। पिछले कुछ दशकों से हिमाचल प्रदेश के नागरिकों की फिटनेस में बहुत कमी आई है। इसका प्रमुख कारण है विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम का न होना। रट्टे वाली पढ़ाई की होड़ में हम विद्यार्थियों की फिटनेस को ही भूल गए हैं। हिमाचल प्रदेश की अधिकांश आबादी गांव में रहती थी। वहां पर सवेरे-शाम वर्षो पहले विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ कृषि व अन्य घरेलू कार्यों में सहायता करता था। विद्यालय आने-जाने के लिए कई किलोमीटर दिन में पैदल चलता था।

कांग्रेस देश के युवाओं को गुमराह कर सेंक रही है राजनीतिक रोटियां : डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल

जयपुर (हिंस)। भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संसद में पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर खुली, व्यापक और सार्थक चर्चा चाहती है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सदन की कार्यवाही बाधित कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है, बल्कि उनकी भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में एनडीए सांसदों ने संसद के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर कांग्रेस द्वारा लगातार सदन नहीं चलने देने का विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा पेपर लीक मामले में व्यापक चर्चा, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई के पक्ष में है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा से बच रहा है। उन्होंने कहा कि जब लोकतांत्रिक तरीके से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, तब कांग्रेस बौखलाहट में संसद की कार्यवाही बाधित कर रही है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की प्राथमिकता युवाओं का भविष्य नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ हासिल

करना है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब वे राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे, तब रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। उस समय उनके इस्तीफे की मांग उठी, लेकिन उन्होंने यह कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था कि परीक्षाएं अधिकारी कराते हैं। उन्होंने कहा कि आज वही डोटासरा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जो उनके दोहरे मापदंड को दर्शाता है। डॉ. अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया कि यदि वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने रीट पेपर लीक प्रकरण के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को मंत्रिमंडल से हटाया था? उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने शासनकाल की जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नवंबर 2021 में जयपुर में आयोजित एक राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं शिक्षकों से सार्वजनिक रूप से पूछा था कि क्या तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जिस पर उपस्थित शिक्षकों ने एक स्वर में *हां* में जवाब दिया था। उस समय गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले अपने शासनकाल के फैसलों और जवाबदेही पर आत्ममंथन करना चाहिए।

भाजपा सरकार पर गहलोत का तंज

बोले, सच पर बुलडोजर चला रही है सरकार

जयपुर (हिंस)। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पेपर लीक को लेकर दिए गए दावों पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री यह दावा करते हैं कि उनके कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि उन्हें यह कहना चाहिए कि किसी भी शिकायत की निष्पक्ष जांच नहीं होने दी गई, ताकि सच्चाई सामने न आ सके। गहलोत ने आरोप लगाया कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट-यूजी के पेपर लीक का केंद्र राजस्थान बना था और लाखों विद्यार्थियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस ने शिकायतों को दबाने का प्रयास किया, जबकि विद्यार्थियों की ओर से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को शिकायत मिलने के बाद मामला सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में नवलगढ़ में आरएएस परीक्षा का प्रश्नपत्र खुले लिफाफे में मिलने, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र खुली सील के साथ पहुंचने, जैसलमेर में एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान कथित नकल प्रकरण तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तकनीकी अधिकारी पर ओएमआर शीट बदलने के आरोपों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई। गहलोत ने कहा कि सरकार अपने कार्यकाल की परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच से बच रही है, क्योंकि जांच होने पर *एक भी पेपर लीक नहीं* का दावा गलत साबित हो जाएगा। उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार सार्वजनिक रूप से भर्ती रद्द करने का श्रेय लेती रही, जबकि अदालत में भर्ती रद्द

नहीं करने की सिफारिश भी सरकार की ओर से की गई थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जवाब मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए गहलोत ने कहा कि उस समय पेपर लीक माफिया के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई थी। उन्होंने दावा किया कि 400 से अधिक गिरफ्तारियां की गईं, माफिया की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, आरपीएससी सदस्य तक जेल भेजे गए तथा पेपर लीक के खिलाफ आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए जुर्माना और संपत्ति जब्ती जैसे प्रावधान वाला सख्त कानून बनाया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो भी कार्रवाई हो रही है, वह उसी कानून के तहत हो रही है। पोस्ट के अंत में गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फर्क साफ है। हमने माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया था, आप सच पर बुलडोजर चला रहे हैं।

महिला सुरक्षा से समझौता नहीं हर शिकायत का होगा त्वरित समाधान : मीना परमार

हिसार (हिंस)। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने हिसार के दौरे के दौरान महिला सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित महिलाओं से जुड़े प्रत्येक मामले का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और आयोग को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए। दौरे के दौरान मीना परमार ने शुक्रवार को केंद्रीय कारागार-2, नागरिक अस्पताल, महिला थाना और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से शिकायत निवारण प्रणाली, काउंसलिंग, चिकित्सा सहायता, कानूनी सेवाओं और अस्थायी आश्रय जैसी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी व्यवस्थाओं में कमियां हैं, उन्हें तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल कागजी रिपोर्ट नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देने वाला सुधार ही आयोग की प्राथमिकता है। वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने कहा कि वन स्टॉप सेंटर हिंसा और उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहारा है। ऐसे में यहां स्वच्छता, सुरक्षा, काउंसलिंग, कानूनी सहायता और अन्य बुनियादी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी केस रजिस्टर और डिजिटल रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट किए जाएं तथा जरूरतमंद महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए। पीड़ित महिलाओं और बच्चों से की सीधी बातचीत मीना परमार ने निरीक्षण के दौरान पीड़ित एवं शोषित महिलाओं और बच्चों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।

हिसार : पेयजल समस्या पर प्रशासन सक्रिय, मटका फोड़ प्रदर्शन स्थगित

हिसार (हिंस)। नजदीकी गांव मैयड़ में लंबे समय से बनी पेयजल संकट की समस्या को लेकर 25 जुलाई को प्रस्तावित मटका फोड़ प्रदर्शन से पहले ही प्रशासन और सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए ग्रामीणों से वार्ता की। सकारात्मक बातचीत और जल्द समाधान के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। हालांकि ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन पहले से अधिक व्यापक रूप में किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की एकजुटता और आंदोलन की चेतावनी के बाद जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता (एसई) ने गांव के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया। इसके बाद हरियाणा सरकार में मंत्री रणबीर गंगवा के पुत्र संजीव गंगवा ने भी 31 सदस्यीय ग्रामीण समिति से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। वार्ता के दौरान अधिकारियों ने गांव की पेयजल समस्या के शीघ्र एवं स्थायी समाधान का भरोसा दिलाया। किसान नेता जोगेंद्र मैयड़ ने शुक्रवार को बताया कि प्रशासन के सकारात्मक आश्वासन को देखते हुए ग्रामीणों ने 25 जुलाई को प्रस्तावित मटका फोड़ प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन वापस नहीं लिया गया है, बल्कि केवल स्थगित किया गया है। यदि प्रशासन अपने वादे पर खरा नहीं उतरता और पेयजल समस्या का समयबद्ध समाधान नहीं करता, तो पूरा गांव दोबारा एकजुट होकर इससे भी बड़ा आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि गांव मैयड़ लंबे समय से पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। अनियमित पेयजल आपूर्ति के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा के कार्यों में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके साथ ही बिजली व्यवस्था को लेकर भी ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले लगभग 24 वर्षों से गांव की बिजली आपूर्ति हिसार कैंट फीडर से होती रही है, लेकिन हाल ही में इसे खरड़ फीडर से जोड़ दिया गया, जिसका गांव में विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि गांव की लगभग आधी भूमि हिसार आर्मी कैंट के निर्माण के लिए दी गई थी, इसलिए बिजली आपूर्ति पहले की तरह हिसार कैंट फीडर से ही बहाल की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने प्रशासन से पानी और बिजली दोनों समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि विकास, बलदेव भाखर, धर्मपाल, मास्टर रमेश, मास्टर मनदीप, गोलू, रामकिशन, अरविंद शर्मा, बलवान वाल्मीकि, रामनिवास नायक, अनुज छोटा नंबरदार, सुरेश लाला, आदेश, दलवीर बिडासरा, सील नाई, नरेंद्र दूत सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।

पेपर लीक के विरोध में जयपुर में छात्रों का प्रदर्शन

जयपुर (हिंस)। दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुए छात्र आंदोलन की गूंज शुक्रवार को जयपुर में भी सुनाई दी। राजधानी के जवाहर सर्किल पर बड़ी संख्या में छात्र-युवा एकत्र हुए और नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में सुधार, युवाओं को रोजगार तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देशभर के छात्रों के भविष्य से जुड़ा आंदोलन है। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र डफली और डमरू बजाते हुए नारे लगा रहे थे, जबकि कई प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का स्केच, भगत सिंह का चित्र और संविधान की प्रति लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से मेहनत करने वाले लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप

था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया और बिना नेम प्लेट वाली वर्दी में मौजूद लोगों द्वारा कार्रवाई की गई। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उनका कहना था कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन के दौरान अनुमति को लेकर उठे सवालों पर छात्रों ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(बी) उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होकर अपनी बात रखने का अधिकार देता है। उनका कहना था कि संविधान ही उन्हें अपनी आवाज उठाने की अनुमति देता है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि आंदोलन में शामिल छात्र अपने संसाधनों से पानी और अन्य आवश्यक सामग्री लेकर आते हैं, लेकिन उनके आंदोलन को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जिम्मेदारीपूर्ण बयान देने की अपील की। एक छात्रा ने आरोप लगाया कि गुरुवार रात एक व्यक्ति चाकू लेकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। छात्रों ने कहा कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, परीक्षा एवं भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार देता है और प्रशासन को युवाओं को प्रदर्शन की अनुमति देनी चाहिए।

लेक्चरर कृषि भर्ती में 40 प्रतिशत क्वालिफाइंग अंक की शर्त को हाईकोर्ट में चुनौती

जोधपुर (हिंस)। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित लेक्चरर स्कूल शिक्षा (कृषि) भर्ती परीक्षा में प्रत्येक प्रश्नपत्र में अलग-अलग 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य करने की शर्त को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डॉ. नूपुर भाटी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता रविंद्र सिंह ने अधिवक्ता बीएल स्वामी के माध्यम से रिट याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता ने एमएससी एग्रीकल्चर प्रथम श्रेणी में 73 प्रतिशत अंकों के साथ तथा बीएड प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। आरपीएससी ने लेक्चरर स्कूल शिक्षा (कृषि) के 500 पदों पर भर्ती के लिए 28 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी किया था। भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान और कृषि विषय के दो प्रश्नपत्र रखे गए हैं।

मत करें चिंता, सबकी समस्या पर होगी प्रभावी कार्रवाई : मुख्यमंत्री योगी

गोरखपुर (हिंस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन, शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन किया। जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर उन्होंने समस्या-शिकायत लेकर आए लोगों को भरोसा देते हुए कहा, *चिंता मत करें, सबकी समस्या पर प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी।* मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां आईं शिकायतों का निस्तारण और समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान करीब 150 लोगों से मिले। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना, उनके प्रार्थनापत्र लिए। उन्होंने पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण निष्पक्ष और समयबद्ध होना चाहिए। अपराध व जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसके साथ ही इलाज के लिए आर्थिक मदद से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर उन्होंने अस्पतालों के इस्टीमेट की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को खूब दुलारा और चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की गोशाला में जाकर गोसेवा की। गोशाला में योगी ने भ्रमण करते हुए कुछ गोवंश को उनके नामों से पुकारा। उनकी आवाज इन गोवंशों के लिए जानी पहचानी है। प्यार भरी पुकार सुनते ही गोवंश दौड़ते हुए उनके पास आ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश के माथे पर हाथ फेरा, उन्हें खूब दुलारा और अपने हाथों से उन्हें गुर खिलाया। उन्होंने मंदिर की गोशाला की अन्य गायों और नंदी को भी अपने हाथों से गुर खिलाया। साथ ही गोशाला के कार्यकर्ताओं को गायों की देखभाल के लिए जरूरी निर्देश दिए।

बिहार के नवादा में आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत, दो महिलाएं झुलसीं

नवादा (हिंस)। बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत सांगोवर गांव में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। घायलों का इलाज नारदीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों में तीन किसान और एक 12 वर्षीय बालक शामिल हैं। सभी लोग खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए खेत में काम कर रहे लोग पास के एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तत्काल नारदीगंज पीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद चार लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद निगरानी में रखा गया है। मृतकों की पहचान शंभू कुमार (45) पिता स्व. चंद्रिका यादव, मदन राजवंशी (50) पिता मुनेश्वर राजवंशी, भुवनेश्वर राजवंशी (50) पिता दुखन राजवंशी तथा सोनू कुमार (12) पिता मिथिलेश प्रसाद, सभी निवासी सांगोवर गांव

के रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान सुनीता देवी, पति स्व. गोविंद यादव तथा शोभी देवी, पति ललित यादव के रूप में की गई है। घटना के बाद सांगोवर गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाने उनके घर पहुंचे। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकारी प्रावधानों के अनुसार मृतकों के परिजनों को आपदा राहत मद से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से बारिश और वज्रपात के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब गूंजेगा राज्य-गीत

चंडीगढ़ (हिंस)। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अब सप्ताह में एक दिन प्रार्थना सभा के दौरान राज्य-गीत की गूंज सुनाई देगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, गौरव और राज्य के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने के उद्देश्य से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत राजकीय विद्यालय में सप्ताह में एक दिन हरियाणा राज्य-गीत का गायन किया जाएगा। साथ ही, विद्यार्थियों को राज्य-गीत के बोल उपलब्ध कराने, एमपी-3 साझा करने और प्रार्थना सभा का संचालन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष अभ्यास कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्य-गीत के नियमित गायन से विद्यार्थियों में प्रदेश की संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली विरासत के प्रति जुड़ाव और सम्मान की भावना मजबूत होगी। इसके लिए सभी विद्यालयों को राज्य-गीत के लिरिक्स और एमपी-3 उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें अधीनस्थ विद्यालयों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि प्रत्येक विद्यालय राज्य-गीत की पर्याप्त प्रतियां विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए तथा आवश्यकता के अनुसार उसका प्रिंट निकालकर वितरित किया जाए। जिन विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन प्रार्थना सभा का संचालन किया जाता है अथवा जो राष्ट्रगान, वंदे मातरम् आदि का नेतृत्व करते हैं, उन्हें राज्य-गीत का विशेष अभ्यास कराया जाएगा ताकि वे इसे प्रभावी और गरिमापूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सकें। निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में हाउस सिस्टम के तहत जिस सदन की प्रार्थना सभा संचालन की जिम्मेदारी होगी, वह सदन राज्य-गीत के नियमित अभ्यास और गायन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगा। साथ ही सभी स्कूल मुखियाओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि राज्य-गीत का नियमित एवं गरिमापूर्ण गायन प्रत्येक सरकारी विद्यालय की प्रार्थना सभा का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। शिक्षा विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों में हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान, प्रदेश के प्रति गर्व और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है।

बिहार विधानसभा में उठा *भूमिहार ब्राह्मण* का मुद्दा, जाति प्रमाण पत्र में नाम बदलने की मांग पर सरकार ने फिलहाल किया इनकार

पटना (हिंस)। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन जाति प्रमाण पत्र और सरकारी अभिलेखों में दर्ज जाति के नाम को लेकर सदन में व्यापक चर्चा हुई। भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने सरकार से मांग की कि जाति प्रमाण पत्रों और सरकारी जाति सूची में केवल *भूमिहार* के स्थान पर *भूमिहार ब्राह्मण* अंकित किया जाए। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस संबंध में कोई नया निर्णय लेने का प्रस्ताव नहीं है। ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से मुद्दा उठाते हुए भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि राज्य के भू-राजस्व अभिलेखों, पुराने सरकारी दस्तावेजों, जिला गजट और अन्य शासकीय रिकॉर्ड में कई स्थानों पर *भूमिहार ब्राह्मण* का उल्लेख मिलता है, जबकि वर्तमान में जारी जाति प्रमाण पत्रों और सरकारी जाति सूची में केवल *भूमिहार* लिखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और प्रमाण पत्र बनवाने में भी व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में विभिन्न सामाजिक संगठनों और लोगों की ओर से सरकार को कई आवेदन दिए जा चुके हैं। उनके अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूर्व में जारी एक पत्र में भी *भूमिहार* के स्थान पर *भूमिहार ब्राह्मण* लिखने का उल्लेख किया गया था। ऐसे में सरकार को सभी सरकारी अभिलेखों और जाति प्रमाण पत्रों में एकरूपता सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार की ओर से जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने उच्च जाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य वर्गों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान सूची में उच्च जातियों के अंतर्गत भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ को अलग-अलग श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर फिलहाल सरकार के समक्ष कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के इस जवाब के बाद सदन में कुछ भूमिहार विधायकों ने असंतोष जताया। भाजपा विधायक विशाल प्रशांत ने सरकार के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि यदि सरकार भूमिहार समुदाय को *भूमिहार ब्राह्मण* के रूप में मान्यता देने को तैयार नहीं है, तो उन्हें अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल कर दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि भूमिहार समाज के अनेक लोग सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तथा सरकार उनकी पारंपरिक पहचान को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर हुई बहस के बाद यह मामला राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया। हालांकि, सरकार ने अपने वर्तमान रुख में किसी बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं।

देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में गिरावट का रुख, चेन्नई में सोने की बढ़ी चमक

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान चेन्नई के अलावा ज्यादातर जगहों पर कमजोरी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। भाव में आई गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 250 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 3200 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। जबकि चेन्नई में सोना 700 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 870 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। वहीं चांदी के भाव में 200 रुपये प्रति किलोग्राम की सांकेतिक कमजोरी नजर आ रही है।

भाव में हुए बदलाव के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,46,170 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,47,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,33,990 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,35,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी मामूली कमजोरी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,46,320 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,140 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,46,170 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,33,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,46,220 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,040 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,47,290 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,35,010 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,46,170 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,33,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,220 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,34,040 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,46,320 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,34,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,220 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,34,040 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,46,320 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,34,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में कमजोरी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,46,170 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,33,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

न्यूज ब्रीफ

ओरिएंट सीमेंट का पहली तिमाही का मुनाफा 62.4 प्रतिशत घटा

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड का मुनाफा सालाना आधार पर 62.4 प्रतिशत घटकर 77 करोड़ रुपये रह गया। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 205 करोड़ रुपये था। अदाणी समूह की अंबुजा सीमेंट्स की अनुषंगी कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 30.25 प्रतिशत घटकर 604 करोड़ रुपये रह गई जो एक साल पहले की समान अवधि में 866 करोड़ रुपये थी। ओरिएंट सीमेंट का कुल खर्च भी 30.11 प्रतिशत घटकर 506 करोड़ रुपये रह गया जबकि पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 724 करोड़ रुपये था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी एक अलग सूचना में बताया कि उसने वेना एनर्जी केएन विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड में 9.04 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। इस 12,34,350 रुपये के सौदे में शेयर और संचयी परिवर्तनीय तरजीही शेयर शामिल हैं।

कंपनी ने बताया कि प्रस्तावित अधिग्रहण 31 अगस्त,

आरबीआई की रियायती विंडो से पहले बैंकों की डालर बान्ड जारी करने की तैयारी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रदान की गई रियायती स्वैप विंडो के दिसंबर में समाप्त होने से पहले कई प्रमुख भारतीय बैंक डालर बान्ड जारी करने की तैयारी में हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कम हेजिंग लागत का लाभ उठाना है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक आफ बड़ौदा (बीओबी) सहित कई बड़े ऋणदाता विदेशी बाजारों से पूंजी जुटाने की योजना बना रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी इस मामले पर विचार कर रहा है। आरबीआई की यह सुविधा पात्र विदेशी मुद्रा बान्ड (ओएफसीबी) और बाहरी कमर्शियल बारोइंग (ईसीबी) पर हेजिंग लागत का 1.5 प्रतिशत तक का हिस्सा कवर करती है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक ने पहले ही 3.3 अरब डालर की फंडिंग में मदद की है। फेडरल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) भी इस दौड़ में शामिल हैं। हालांकि, पहले एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जैसे बड़े बैंकों द्वारा डालर बान्ड जारी करने से बाजार में एक सुस्ती देखी गई थी। निवेशकों को भारी आपूर्ति की आशंका थी, जिससे क्रेडिट स्प्रेड में वृद्धि हुई और फंडिंग की लागत कम आकर्षक हो गई। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और बान्ड स्प्रेड जैसे कारकों को रियायती सुविधा में शामिल न होने के कारण, रुपये में फंडिंग की प्रभावी लागत घरेलू उधार के समान ही थी। बाजार के जानकारों के अनुसार, जून तिमाही के नतीजों से पहले कई बैंकों का साइलेंट पीरियड में होना भी एक कारण था। अब अधिकांश निजी बैंक अपने नतीजे घोषित कर चुके हैं और विदेशी बान्ड बाजार में उतरने के लिए तैयार हैं। वे बान्ड जारी करने के समय और लागत पर सावधानीपूर्वक विचार कर रहे हैं, ताकि विदेशी पूंजी घरेलू उधार से अधिक लाभदायक हो। जुटाई गई धनराशि का उपयोग मुख्यत: बैंकों की बैलेंस शीट के जरिए एनआरआई जमाकर्ताओं को लिवरेज सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

भारत में आईफोन 17 सीरीज का दबदबा, एप्पल के शिपमेंट में 44 प्रतिशत हिस्सेदारी

मुंबई। एप्पल की आईफोन 17 सीरीज ने 2026 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाई हैं, जो कंपनी के कुल आईफोन शिपमेंट में 44 प्रतिशत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन लाइनअप बन गया। एक रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, आईफोन 16 सीरीज 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि आईफोन 17ई का योगदान 6 प्रतिशत और आईफोन 16ई का 5 प्रतिशत रहा। पुरानी आईफोन 15 सीरीज भी 4 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखने में सफल रही। रिपोर्ट में बताया गया हैं कि अप्रैल-जून तिमाही आमतौर पर एप्पल के लिए मौसमी रूप से धीमी रहती है।

कच्चे तेल की तेजी से बिगड़ा ग्लोबल मार्केट का मूड, एशिया में चौतरफा बिकवाली का दबाव

नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आई जोरदार तेजी की वजह से ग्लोबल मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर के ज्यादातर शेयर बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार बिकवाली होती रही। डाउ जान्स फ्यूचर्स भी मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान कमजोरी का रुख बना रहा। वहीं एशियाई बाजार में चौतरफा बिकवाली होती हुई नजर आ रही है।

अमेरिका में महंगाई बढ़ने के संकेत और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आए जोरदार उछाल की वजह से वाल स्ट्रीट के सूचकांक पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुए। डाउ जान्स इंडस्ट्रियल एवरेज 506.93 अंक यानी 0.97 प्रतिशत लुढ़क कर 51,711.65 अंक के स्तर पर आ गया। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 90.66 अंक यानी 1.21 प्रतिशत टूट कर 7,408.30 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 553.21 अंक यानी 2.15 प्रतिशत की जोरदार कमजोरी के साथ 25,137.69 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.01 प्रतिशत की सांकेतिक गिरावट के साथ 51,704.15 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.73 प्रतिशत फिसल कर 10,639.17 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 138.80 अंक यानी 1.67 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 8,299.09 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 392.29 अंक यानी 1.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,763.12 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में चौतरफा दबाव बना हुआ है। एशिया के सभी नौ बाजार में गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी 167 अंक यानी 0.70 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,695.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,558.92 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। कोस्पी इंडेक्स जबरदस्त दबाव में नजर आ रहा है। यह सूचकांक फिलहाल 404.22 अंक यानी 5.70 प्रतिशत लुढ़क कर 6,692.27 अंक के स्तर पर आ गया है। निक्केई इंडेक्स में भी जबरदस्त गिरावट नजर आ रही है। फिलहाल यह सूचकांक 2,032.60 अंक यानी 3.06 प्रतिशत फिसल कर 64,390 अंक के स्तर तक गिर गया है। ताइवान वेटेड इंडेक्स में भी जबरदस्त कमजोरी नजर आ रही है। फिलहाल यह सूचकांक 1,038.20 अंक यानी 2.31 प्रतिशत टूट कर 45,812.61 अंक के स्तर पर आया हुआ है।

जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स भी दो प्रतिशत से अधिक गिर चुका है। फिलहाल यह सूचकांक 144.07 अंक यानी 2.28 प्रतिशत लुढ़क कर 6,171.24 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा हैंग सेंग इंडेक्स 311.81 अंक यानी 1.24 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,899 अंक के स्तर पर, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,830.19 अंक के स्तर पर और सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.24 प्रतिशत टूट कर 1,637.13 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

एयर इंडिया और सऊदिया एयरलाइंस ने कोडशेयर विस्तार के लिए किया समझौता

नई दिल्ली

टाटा की अगुवाई वाली एयर इंडिया और सऊदी अरब की सऊदिया एयरलाइंस ने अपनी रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों एयरलाइंस के बीच कोडशेयर समझौते का विस्तार, नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार करने और व्यापक वाणिज्यिक सहयोग की संभावनाओं को तलाशने की योजना है।

एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जारी पोस्ट में कहा कि हमने अपनी मौजूदा कोडशेयर डील को आगे बढ़ाते हुए और आपरेशनल व कमर्शियल सहयोग के नए मौके बनाते हुए, अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए सऊदिया एयरलाइंस के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है।

एयरलाइन ने बताया कि इस समझौते पर सऊदी समूह के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर इब्राहिम अल-ओमर और एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक मिस्टर कैंपबेल विल्सन ने हस्ताक्षर किए हैं।

एयर इंडिया ने कहा कि हम साथ मिलकर अपने नेटवर्क में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, कस्टमर एक्सपीरियंस और लायल्टी के मामले में सहयोग को गहरा करने व भारत, सऊदी अरब और अन्य जगहों के बीच यात्रा करने वालों के लिए ज्यादा वैल्यू बनाने का लक्ष्य रखते हैं। एयरलाइन ने कहा कि यह एमओयू हमारे संबंधित ग्रुप्स की अन्य एयरलाइंस (जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस और फ्लाईडील) तक इस पार्टनरशिप को बढ़ाने की संभावना तलाशने की नींव भी रखता है, जिससे हमारे यात्रियों के लिए और भी बेहतर कनेक्टिविटी और विकल्प बनेंगे। गौरतलब है कि भारत और सऊदी अरब के बीच यात्री यातायात लगातार बढ़ रहा है।

अब रसोई में भी इथेनाल, एलपीजी पर निर्भरता घटाने की तैयारी

नई दिल्ली। पेट्रोल में इथेनाल मिश्रण (ई20) की सफलता के बाद केंद्र सरकार अब घरेलू रसोई के लिए इथेनाल-आधारित कुकिंग फ्यूल का विकल्प लाने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय इस नीति पर काम कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य एलपीजी आयात पर निर्भरता कम करना और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना है। सरकार मानती है कि इथेनाल एक स्वच्छ जैव ईंधन है, जो कार्बन उत्सर्जन घटाएगा। इसकी बढ़ती मांग से गन्ना व अन्य फसलों से जुड़े किसानों को लाभ मिलेगा और घरेलू ईंधन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, यह योजना अभी शुरुआती चरण में है। मंत्रालय को इथेनाल स्टोव, आपूर्ति प्रणाली, सुरक्षा मानक और आम उपभोक्ता तक पहुंच जैसे कई पहलुओं पर काम करना बाकी है। सुरक्षित व सुविधाजनक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नीति लागू करने से पहले गहन तकनीकी जांच और विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेट्रोल में ई20 से अधिक इथेनाल की मात्रा बढ़ाने पर अभी कोई नया फैसला नहीं लिया गया है। भविष्य में किसी भी बदलाव से पहले वैज्ञानिक अध्ययन और व्यापक चर्चा होगी। कुल मिलाकर, यह पहल देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी और बायोफ्यूल मिशन को नई रफ्तार देगी।

कई देशों से बाहर होने की अटकलों को वनप्लस ने किया खारिज

नई दिल्ली

स्मार्टफोन निर्माता वनप्लस कंपनी की मूल कंपनी ओप्पो अपने वैश्विक कारोबार का पुनर्गठन करते हुए ब्रांड रणनीति में बदलाव पर विचार कर रही है। कंपनी द्वारा भारत, अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों से अपने परिचालन समेटने की अटकलों ने तकनीकी जगत में हलचल पैदा कर दी है। वहीं वनप्लस ने ऐसी खबरों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि कंपनी प्रमुख वैश्विक बाजारों में अपने परिचालन जारी रखेगी।

रिपोर्ट में कहा गया था कि ओप्पो अपने ब्रांड पोर्टफोलियो को सरल बनाने की योजना के तहत भविष्य में कुछ बाजारों में वनप्लस ब्रांड को सीमित कर सकती है और प्रीमियम स्मार्टफोन श्रेणी में ओप्पो ब्रांड को अधिक मजबूत बनाने पर ध्यान दे सकती है। यह दावा एक जर्मन प्रकाशन की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, जिसके बाद कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रकाशित किया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में वनप्लस और ओप्पो के हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यों का व्यापक एकीकरण हो चुका है। दोनों कंपनियों के आपरेटिंग सिस्टम भी पहले की

तुलना में काफी हद तक एक-दूसरे के करीब आ चुके हैं। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि लागत कम करने और व्यावसायिक रणनीति को सरल बनाने के लिए भविष्य में ब्रांड संरचना में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि, वनप्लस ने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि भारत, यूरोप और अन्य प्रमुख बाजार कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि वह इन क्षेत्रों में अपने उत्पादों की बिक्री, सेवाओं और नए स्मार्टफोन लान्च को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा परिचालन बंद करने की कोई योजना नहीं है। भारत वनप्लस के सबसे बड़े बाजारों में शामिल है, जहां कंपनी ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोनों के साथ-साथ नार्ड श्रृंखला के जरिए मिड-रेंज वर्ग में भी मजबूत पहचान बनाई है।

कमजोर मानसून का असर : त्योहारों से पहले गेहूं होगा और महंगा प्रमुख मंडियों में एक महीने में 7.5% तक बढ़े दाम

नई दिल्ली

त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले देश के हाजिर बाजारों में गेहूं की कीमतों में फिर तेजी लौटने लगी है। मानसून की सुस्त रफ्तार, जलाशयों में घटता जलस्तर और आगामी रबी सीजन की बुआई को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच बीते एक महीने में देश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के दाम 3.8 फीसदी से लेकर 7.5 फीसदी तक बढ़ चुके हैं। कम आवक और खुले बाजार में सरकारी बिक्री शुरू होने में हो रही देरी ने कीमतों को और हवा दी है। व्यापारियों और बाजार विश्लेषकों का मानना है कि जब तक सरकार अपने बफर स्टाक से खुले बाजार में गेहूं की बिक्री शुरू नहीं करती, तब तक गेहूं के साथ-साथ आटा और मैदा भी महंगे हो सकते हैं।

आखिर कमजोर मानसून से गेहूं पर संकट क्यों गहराने लगा है – इस साल मानसून के दौरान बारिश सामान्य से कम रही है। कोटा के कारोबारी रवि मेहता के मुताबिक, कम बारिश के कारण जलाशयों का जलस्तर घटने की आशंका है। इसका सीधा असर रबी सीजन की सिंचाई पर पड़ सकता है, जिससे गेहूं की बुआई और उत्पादन दोनों प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है।

सरकारी बिक्री में देरी से बाजार पर क्या असर पड़ रहा है नवी मुंबई के थोक व्यापारी देवेंद्र वोरा का कहना है कि सरकार ने गेहूं और चावल के लिए रिजर्व प्राइस तो घोषित कर दिए हैं, लेकिन खुले बाजार में गेहूं की नीलामी अभी तक शुरू नहीं की गई है। उनका अनुमान है कि सरकार त्योहारी सीजन के चरम पर पहुंचने के बाद, यानी करीब एक महीने बाद, बिक्री शुरू कर सकती है। इस देरी के कारण खुले बाजार में आपूर्ति सीमित बनी हुई है, जिससे कीमतों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है।

त्योहारी मांग और कम आवक से दाम क्यों चढ़ रहे हैं इंदौर के व्यापारी गौरव कोचर के अनुसार, दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले गेहूं की मांग तेजी से बढ़ने लगती है, जबकि मंडियों में नए माल की आवक अपेक्षाकृत कम है। मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर की वजह से गेहूं की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है।

विदेश में एलआरएस के तहत मई में 2.39 अरब डालर भेजे

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मई महीने में उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेश भेजा गया धन सालाना आधार पर 3.6 फीसदी बढ़कर 2.39 अरब डालर हो गया, जो अप्रैल की तुलना में 4.8 फीसदी अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से विदेश में निवेश संबंधी गतिविधियों में उछाल के कारण हुई है, जबकि यात्रा और शिक्षा जैसे पारंपरिक खर्चों में कमी देखी गई है। मई में रेमिटेंस से जुड़ी जमा राशि दोगुनी से अधिक होकर 1,181.2 लाख डालर रही। इसी तरह इक्विटी/डेट की खरीद में रेमिटेंस भी दोगुना बढ़कर 3,636 लाख डालर हो गया, जो कुल वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि भारतीय नागरिक अब विदेश में अधिक निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। इसके विपरीत, अचल संपत्ति खरीद के लिए धन 14.22 फीसदी घटकर 357.6 लाख डालर रहा। सबसे बड़ी श्रेणी, विदेश यात्रा संबंधी रेमिटेंस भी 7.7 फीसदी घटकर 1.28 अरब डालर पर आ गया। इसी तरह, शिक्षा के लिए धन 38 फीसदपी घटकर 926.1 लाख डालर और उपहार के लिए 13.6 फीसदी घटकर 2,015 लाख डालर रह गया। इन गिरावटों के बावजूद, निवेश संबंधी गतिविधियों में वृद्धि ने कुल एलआरएस प्रवाह को बढ़ाया है। 2004 में शुरू हुई एलआरएस योजना भारतीयों को एक वित्त वर्ष में 2,50,000 डालर तक विदेश भेजने की अनुमति देती है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन सहित सबसे अधिक रन बनाने वाले पांच खिलाड़ी

मुम्बई

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में पहले नंबर पर हैं। तेंदुलकर को संन्यास लिए एक दशक से भी अधिक समय जो गया है पर कोई भी खिलाड़ी उनके बनाये रनों के रिकार्ड के तोड़ नहीं पाया है। टेस्ट, एकदिवसीय और टी20 अंतरराष्ट्रीय तीनों प्रारूपों को मिलाकर, सचिन ने अपने 24 वर्ष के अद्वितीय करियर में कुल 34,357 रन बनाए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर भारत के ही अनुभवी विराट कोहली हैं, इसके बाद श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा, आस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग और श्रीलंका के ही माहेला जयवर्धने का नंबर आता है। इस सभी ने विश्वक्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया है पर इसके बाद भी सचिन का रिकार्ड नहीं तोड़ पाये हैं। इनमें से अब केवल विराट ही सक्रिय क्रिकेट हैं जो एकदिवसीय प्रारुप में खेल रहे हैं। ऐसे में अब केवल विराट के पास ही उनके रिकार्ड को तोड़ने का अवसर है।

गौरतलब है कि तेंदुलकर ने साल 1989 से 2013 के बीच भारत के लिए कुल 664 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। इनमें उन्होंने 782 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 74 बार नाबाद रहकर 48.52 की प्रभावशाली औसत से 34,357 रन बटोरे। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 248 रन रहा। उनके नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक और 164 अर्धशतक दर्ज हैं, जो आज भी विश्व रिकार्ड हैं और उनकी अद्वितीय बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाते हैं। अपने करियर में उन्होंने 50,000 से अधिक गेंदों का सामना किया और उनके चार हजार से ज्यादा चौके तथा 264 छक्के लगाये।

वहीं विराट दूसरे नंबर पर हैं। वह सचिन के रिकार्ड के सबसे करीब पहुंचे है। वर्ष 2008 से अब तक अपने शानदार करियर में कोहली ने 562 मैचों की 629 पारियों में 91 बार नाबाद रहते हुए 52.71 की असाधारण औसत से 28,359 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 254 रन है। विराट के नाम 85 शतक और 148 अर्धशतक दर्ज हैं। 79.73 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले विराट को आधुनिक क्रिकेट के सबसे सफल और प्रभावशाली बल्लेबाजों में से एक माना जाता है, और उनके पास अभी भी सचिन के रिकार्ड को चुनौती देने का अवसर अवसर है।

तीसरे स्थान पर श्रीलंका के महान विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार संगकारा हैं, जिन्होंने 2000 से 2015 के बीच 594 मैचों की 666 पारियों में 46.77 की औसत से 28,016 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 319 रन रहा। संगकारा ने 63 शतक और 153 अर्धशतक लगाए हैं। आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दो बार के विश्व कप विजेता पोंटिंग इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 1995 से 2012 तक 560 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 668 पारियों में 45.95 की औसत से 27,483 रन बनाए। पोंटिंग ने अपने करियर में 71 शतक और 146 अर्धशतक लगाएहै। पांचवें स्थान पर श्रीलंका के एक और दिग्गज बल्लेबाज माहेला जयवर्धने हैं, जिन्होंने 1997 से 2015 तक 652 अंतराष्ट्रीय मैचों की 725 पारियों में 40.81 की औसत से 25,957 रन बनाए।

न्यूज़ ब्रीफ

विश्वनाथन आनंद बने फिडे के अंतरिम अध्यक्ष, प्रतिबंधों के बाद अर्कादी द्वोर्कोविच ने छोड़ा पद

नई दिल्ली। भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी और पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिडे के अध्यक्ष अर्कादी द्वोर्कोविच के यूरोपीय संघ (ईयू) की प्रतिबंध सूची में शामिल होने के बाद उनके पद से हटने के फैसले के पश्चात आनंद ने यह जिम्मेदारी संभाली है। फिडे ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि फिडे चार्टर के अनुच्छेद 19.2 के तहत उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक द्वोर्कोविच पर स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ के लागू प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे। फिडे के नए अध्यक्ष का चुनाव सितंबर में होना है। फिडे ने अपने बयान में कहा कि संगठन ने द्वोर्कोविच के निर्णय को स्वीकार कर लिया है और अध्यक्ष के रूप में उनके सभी अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार निलंबित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही वे किसी भी रूप में फिडे या उसकी परिसंपत्तियों का संचालन या नियंत्रण नहीं कर सकेंगे। यूरोपीय संघ ने रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़े मामलों में अपने 21वें प्रतिबंध पैकेज के तहत द्वोर्कोविच सहित 48 व्यक्तियों और 170 संस्थाओं को प्रतिबंध सूची में शामिल किया है। यह पिछले चार वर्षों में यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा प्रतिबंध पैकेज माना जा रहा है। रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री (2012-2018) रह चुके द्वोर्कोविच ने कहा कि वह यूरोपीय संघ के इस फैसले को सभी कानूनी माध्यमों से चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से अपने दायित्वों को निलंबित किया है ताकि फिडे के कामकाज पर किसी तरह का असर न पड़े। द्वोर्कोविच ने कहा, मुझे फिडे परिषद पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि परिषद और प्रशासन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए फिडे के टूर्नामेंटों, सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों को निर्बाध रूप से जारी रखेंगे।

बांदा के मोहम्मद अर्श ने राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक

बांदा। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के होनहार बैडमिंटन खिलाड़ी मोहम्मद अर्श ने चेन्नई (तमिलनाडु) में आयोजित योनैक्स-सनराइज अखिल भारतीय सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता-2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीनियर पुरुष युगल वर्ग में कांस्य पदक जीतकर जिले और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। देशभर के शीर्ष खिलाड़ियों की मौजूदगी वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में मोहम्मद अर्श ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और कांस्य पदक अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि से खेल जगत और पूरे जनपद में खुशी की लहर है। खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और जनपदवासियों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उवल भविष्य की कामना की है। मोहम्मद अर्श के पिता मो. अशफाक बांदा शहर के बलखंडी नाका क्षेत्र के निवासी हैं और फैशन टेलर का कार्य करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद अर्श ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर यह उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

ईसीबी ने 2027 एशेज सीरीज का कार्यक्रम जारी किया, 18 जून से ट्रेंट ब्रिज में शुरु होगी पुरुषों की टेस्ट सीरीज

लंदन। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने अगले साल 2027 में होने वाली एशेज सीरीज का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जहां इंग्लैंड की पुरुष टीम अगले साल 18 जून से ट्रेंट ब्रिज में आस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने एशेज अभियान की शुरुआत करेगी। वहीं महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत 24 जून से हेडिंग्ले में करेगी। पुरुषों की पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 18 जून को ट्रेंट ब्रिज में शुरू होगी। इसके बाद उसे लार्ड्स, एजबेस्टन और यूटिलिटा बाउल (साउथेम्प्टन) में खेलना है। इस प्रतिष्ठित सीरीज का समापन 29 जुलाई का द ओवल में होगा। यह सीरीज 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगी। वहीं इंग्लैंड की महिला टीम अपने एशेज अभियान की शुरुआत 24 जून को हेडिंग्ले में एक टेस्ट मैच के साथ करेगी। यह 2001 के बाद लीड्स में आयोजित होने वाला पहला महिला एशेज टेस्ट होगा, जिससे ये मुकाबला और भी खास बन जाएगा।

भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुआ ग्लास्गो कामनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज

ग्लास्गो,

स्कॉटलैंड के ग्लास्गो स्थित हाइड्रो एरिना में गुरुवार रात रंगों, रोशनी, संगीत और सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत संगम के बीच कामनवेल्थ गेम्स 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। पारंपरिक स्कॉटिश संस्कृति और आधुनिक तकनीक के शानदार मेल ने उद्घाटन समारोह को यादगार बना दिया। हजारों दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों, आकर्षक दृश्य प्रभावों और खिलाड़ियों की शानदार परेड ने खेलों के महाकुंभ की बेहतरीन शुरुआत की।

समारोह की शुरुआत स्कॉटलैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के साथ हुई। देश के महानतम खिलाड़ियों में शुमार दिग्गज ट्रैक साइकिलिस्ट सर क्रिस होय और प्रसिद्ध अभिनेता ग्रेग मैकह्यू लोकप्रिय ब्रिटिश विज्ञान-कथा श्रृंखला डाक्टर हू के मशहूर टार्डिस बाक्स के माध्यम से मंच पर पहुंचे। इस दौरान किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला की मौजूदगी ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया। टार्डिस को इस बार स्कॉटलैंड की कहानी और विरासत को दुनिया तक पहुंचाने के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

इसके बाद संगीत, नृत्य और आधुनिक तकनीक का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने पूरे एरिना को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्काटिश इलेक्ट्रानिक फोक संगीतकारों वाल्टोस की धुनों पर तैयार विशेष साउंडट्रैक के बीच 74 राष्ट्रमंडल खेल संघों के खिलाड़ी एक-एक कर एरिना में प्रवेश करते गए। एलईडी स्क्रीन पर हर दल का परिचय दिया गया, जबकि स्काटलैंड की प्राकृतिक वनस्पतियों से प्रेरित रंग-बिरंगे एनिमेशन के जरिए राष्ट्रमंडल बैटन को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया।

मेजबान स्काटलैंड का दल सबसे आखिर में मैदान में उतरा और घरेलू दर्शकों ने जोरदार तालियों और नारों के साथ उसका स्वागत किया। खिलाड़ियों की परेड ने पूरे समारोह का सबसे भावुक और आकर्षक पल पेश किया, जहां खेल भावना, एकता और राष्ट्रमंडल परिवार की विविधता साफ दिखाई दी।

उद्घाटन समारोह में स्काटलैंड की लोककथाओं और इतिहास को भी आधुनिक अंदाज में मंच पर उतारा गया। प्रसिद्ध लोच नेस मान्स्टर की कहानी से लेकर ग्लास्गो की पहचान मानी जाने वाली वायस आफ टाइम घड़ी तक, हर प्रस्तुति ने दर्शकों को स्काटलैंड की सांस्कृतिक यात्रा से रूबरू कराया। गायक नाथन इवांस के जोशीले प्रदर्शन, ग्लास्गो सेंट्रल स्टेशन पर आधारित रंगारंग नृत्य और शहर के जहाज निर्माण, वस्त्र उद्योग, रेल इंजन तथा भाप इंजनों की ऐतिहासिक विरासत को भी शानदार अंदाज में प्रस्तुत किया गया। प्रसिद्ध गायक कैलम बीटी ने लोकप्रिय गीत यस सर, आई कैन बूगी की प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, जबकि गायिका नीना नेसबिट ने वर्ष 1988 के चर्चित स्काटिश गीत आई एम गोना बी (500 माइल्स) को अपनी भावपूर्ण आवाज में प्रस्तुत कर पूरे माहौल को भावुक बना दिया। समारोह के दौरान कामनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे और ग्लास्गो 2026 के चेयरमैन जार्ज ब्लैक ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेल केवल खिलाड़ियों के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के खेल हैं और इनका उद्देश्य खेलों के माध्यम से देशों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधना है। अंत में किंग चार्ल्स ने आधिकारिक रूप से कामनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन की घोषणा की। इसके साथ ही 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाले इस बहु-खेल आयोजन का औपचारिक आगाज हो गया, जिसमें राष्ट्रमंडल के देशों के हजारों खिलाड़ी पदकों के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे।

अर्जेंटीना के अनुभवी डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबाल को कहा अलविदा

बूनस आयर्स

अर्जेंटीना के अनुभवी डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय फुटबाल से संन्यास की घोषणा कर दी। इसके साथ ही 38 वर्षीय खिलाड़ी के 17 साल लंबे शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत हो गया। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना को 2022 फीफा विश्व कप और दो कोपा अमेरिका खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई।

ओटामेंडी ने अर्जेंटीना के लिए 139 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और चार फीफा विश्व कप में देश का प्रतिनिधित्व किया। वह हाल ही में अमेरिका में आयोजित फीफा विश्व कप 2026 में उपविजेता रही अर्जेंटीना टीम का भी हिस्सा थे। फाइनल में अर्जेंटीना को स्पेन के हाथों अतिरिक्त समय में 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था।

संन्यास की घोषणा करते हुए ओटामेंडी ने इंस्टाग्राम पर भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, मुझे अपने करियर के सबसे कठिन शब्द लिखने पड़ रहे हैं। किस्मत ने ऐसा लिखा कि मेरा आखिरी मैच विश्व कप फाइनल रहा। परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन मैं गर्व के साथ विदा ले रहा हूं क्योंकि इस टीम ने आखिरी सेकंड तक अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अर्जेंटीना, मुझे विश्व चैंपियन बनने का सपना पूरा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

हाल ही में ओटामेंडी ने यूरोप में 16 साल का सफल करियर समाप्त करने के बाद अर्जेंटीना के दिग्गज क्लब रिवर प्लेट से जुड़ने का फैसला किया। यूरोप में उन्होंने पोर्टो, वेलेंसिया, मैनचेस्टर सिटी और बेनफिका जैसे बड़े क्लबों का प्रतिनिधित्व किया और कई यादगार सफलताएं हासिल कीं।

अपने मजबूत रक्षात्मक खेल, नेतृत्व क्षमता और जुझारू अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले ओटामेंडी को अर्जेंटीना फुटबाल के सबसे सफल डिफेंडरों में गिना जाता है। उनके संन्यास के साथ अर्जेंटीना फुटबाल के एक स्वर्णिम अध्याय का भी समापन हो गया।

इंग्लैंड में घरेलू वनडे क्रिकेट में होगा स्टोक्स और कुलदीप का मुकाबला

लंदन। इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने एक दशक से अधिक समय के बाद घरेलू वनडे क्रिकेट में धमाकेदार वापसी करते हुए डरहम की ओर से नाबाद शतक लगाकर दिखाया है कि वह अभी भी एक मैच विजेता खिलाड़ी हैं। वहीं अब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें 31 जुलाई पर टिकी हैं, जब क्लिफ्टन पार्क ग्राउंड, यार्क में डरहम का सामना यार्कशायर से होगा। यह मुकाबला सिर्फ दो काउंटी टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं होगी, बल्कि इसमें स्टोक्स का सामना भारतीय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव से होगा। कुलदीप यादव के लिए यह टूर्नामेंट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई एकदिवसीय सीरीज में उन्हें भारतीय टीम में शामिल होने के बावजूद एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था, जिस पर कई क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों ने सवाल उठाए थे। उनकी गैरमौजूदगी को लेकर काफी आलोचना भी हुई थी, क्योंकि वे अपनी फिरकी से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में, वन-डे कप कुलदीप के लिए अपनी लय वापस पाने, अपनी गेंदबाजी का जौहर दिखाने और चयनकर्ताओं को यह याद दिलाने का एक सुनहरा मौका होगा कि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में कितने प्रभावी हो सकते हैं। वह निश्चित रूप से यार्कशायर के लिए खेलते हुए अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे और आगामी अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे।

एफआईएच यूथ हाकी5एस एशियाई चैंपियनशिप: भारतीय पुरुष और महिला टीमों का विजयी अभियान जारी

मस्कट (ओमान)

एफआईएच यूथ हाकी5एस एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय सब-जूनियर महिला और पुरुष टीमों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। गुरुवार को खेले गए एलीट पूल के मुकाबलों में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 10-0 से रौंद दिया, जबकि पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 8-3 से हराकर लगातार जीत का सिलसिला बरकरार रखा।

महिला वर्ग में भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। नौशीन नाज़ ने मुकाबले के पहले ही मिनट में लगातार दो गोल दागकर भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ तक भारतीय टीम इसी बढ़त के साथ आगे रही, लेकिन दूसरे हाफ में उसने खेल की रफ्तार और तेज करते हुए आठ और गोल दागकर कजाकिस्तान को पूरी तरह मुकाबले से बाहर कर दिया।

प्लेयर आफ द मैच संदीपा कुमारी ने 11वें, 16वें और 18वें मिनट में गोल कर हैट्रिक पूरी की। नौशीन नाज़ ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 1वें, 1वें, 15वें और 20वें मिनट में चार गोल दागे। इसके अलावा किरण एक्का (15वें), नीलम टोपनो (17वें) और पुष्पा मांझी (19वें मिनट) ने भी गोल कर भारत की एकतरफा जीत सुनिश्चित की।

पुरुष वर्ग में भारत और बांग्लादेश के बीच पहले हाफ में कांटे की टक्कर देखने को मिली। भारतीय कप्तान और प्लेयर आफ द मैच केतन कुशवाहा ने चौथे और आठवें मिनट में दो गोल किए, जबकि शाहरुख अली ने तीसरे मिनट में एक गोल कर भारत को 3-2 की बढ़त दिलाई। बांग्लादेश के लिए मोहम्मद होसेन (6वें) और सोहराब सोटोन (8वें मिनट) ने गोल कर मुकाबला रोमांचक बनाए रखा। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी रही। केतन कुशवाहा ने 12वें और 15वें मिनट में दो और गोल कर अपनी चार गोल की उपलब्धि पूरी की। वहीं रोमित पाल (13वें), प्रहलाद राजभर (14वें) और राहुल यादव (18वें मिनट) ने भी एक-एक गोल किया। बांग्लादेश की ओर से सोहराब सोटोन ने 11वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके।

श्रेयस अय्यर शुरुआती 8 मैचों में लगातर टास जीतने वाले विश्व के पहले कप्तान बने

हरारे

भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ यहां पहले ही मैच में एक नया रिकार्ड अपने नाम किया है। इस मैच में टास जीतते ही श्रेयस शुरुआती आठ मैचों में में टास जीतने वाले पहले भारत और विश्व क्रिकेट के पहले कप्तान बन गये हैं। किसी अन्य कप्तान के नाम ये रिकार्ड नहीं है।

इस अनूठी उपलब्धि के साथ ही उन्होंने बहामास के ग्रेगरी टेलर का रिकार्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले टेलर ने बतौर कप्तान अपने शुरुआती टी20 मैचों में टास जीते थे।

गौरतलब है कि सूर्यकुमार यादव की जगह टी20 टीम की कप्तानी संभालने के बाद से ही श्रेयस अय्यर का अब तक का सफर मैच परिणाम की नजर से भले ही अच्छा नहीं रहा है पर टास हमेशा उन्होंने ही जीता है। इसकी शुरुआत आयरलैंड दौरे से हुई थी, जहां बेलफास्ट में उन्होंने दो बार टास जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। इसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के कड़े दौरे पर पहुंची, जहां इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक के खिलाफ भी श्रेयस ने ही टास जीते। चेस्टर-ले-स्ट्रीट, मैनचेस्टर, नाटिंघम, ब्रिस्टल और साउथैम्प्टन में लगातार पांचों मैचों में टास जीतकर श्रेयस ने सीरीज अपने नाम की।

श्रेयस अय्यर की यह उपलब्धि सिर्फ टी20 फार्मेट तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (टेस्ट, एकदिवसीय और टी20 मिलाकर) के 88 साल पुराने एक ऐतिहासिक रिकार्ड की बराबरी भी कर ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान अपने डेब्यू के बाद से लगातार सबसे ज्यादा टास जीतने के मामले में अय्यर अब इंग्लैंड के महान खिलाड़ी वाली हैमंड की बराबर पर आ खड़े हुए हैं, जिन्होंने 1938 में बतौर कप्तान अपने शुरुआती 8 अंतरराष्ट्रीय मैचों में टास जीते थे। इस सूची में श्रेयस और वाली हैमंड के बाद बहामास के ग्रेगरी टेलर (7 टास) और पाकिस्तान के शादाब खान (5 टास) का नंबर आता है।

वहीं भारत की बात की जाये तो टी20 प्रारुप में लगातार सबसे ज्यादा टास जीतने का रिकार्ड अब तक पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम दर्ज था, जिन्होंने मई 2010 से फरवरी 2012 के बीच बतौर भारतीय टी20 कप्तान लगातार 7 टास जीते थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ आठवां टास जीतते ही श्रेयस ने धोनी के इस 14 साल पुराने रिकार्ड को तोड़ दिया और भारत के सबसे सफल टास-विजेता कप्तान बन गए। अब उनकी नजर पूर्ण सदस्य देशों के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा टास जीतने के विश्व रिकार्ड पर है। ये रिकार्ड अभी वेस्टइंडीज के दो बार के टी20 विश्व कप विजेता कप्तान डैरेन सैमी के नाम है, जिन्होंने लगातार 10 टास जीते थे।

इस उम्र में न करें जिमिंग

आकर्षक दिखने और मस्कुलर बॉडी की चाह में लड़के व लड़कियां दोनों ही आजकल कम उम्र में जिम जाकर वर्कआउट करना पसंद करने लगे हैं। ऐसे में वे फिजिकली मजबूत तो हो जाते हैं लेकिन शरीर में जो बदलाव नेचुरल तरीके से होने चाहिए वे नहीं होते। जिससे मांसपेशियों में खिंचाव होने के साथ हड्डियों की सही ग्रोथ नहीं होती और हार्मोन्स ठीक से रिलीज न होने के कारण हार्मोन इंबेलेंस की समस्या सामने आती है। 20 की उम्र तक सामान्यतः लंबाई बढ़ाने वाली हड्डियों में फ्यूजन होने से लंबाई बढ़ने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। लड़कों में वॉइस बॉक्स पूरी तरह विकसित हो जाता है। लंबाई बढ़ने की प्रक्रिया बंद होते ही किशोर के स्वभाव में बदलाव आने इस उम्र में लगभग बंद हो जाते हैं जिससे उसका गुस्सा शांत रहता है और वह हर बात का सोच-समझकर जवाब देता है। उम्र के मुताबिक वजन, लंबाई के अनुसार न हो तो रोगों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में लड़कियों में माहवारी का अनियमित होना और पीसीओडी की दिक्कत ज्यादा होती है। यदि खानपान की आदत खराब है तो उसे ओबेसिटी भी हो सकती है जो भविष्य में उसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग आदि से घेर सकती है। कुछेक मामलों में कम हाइट भी परेशानी पैदा करती है।

सतर्कता बरतें

खानपान में जंक व फास्ट फूड के बजाय पौष्टिक चीजों को चुनें। इस उम्र में सही-गलत को पहचानने की समझ बच्चे में विकसित हो रही होती है इसलिए माता-पिता सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, ड्रग्स आदि से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं। उसका डेली रुटीन सही हो, जिसमें उसे समय पर सोने व उठने, भोजन करने, पढ़ने, आराम करने व तनाव से दूर रहने की सलाह दी जाए। लड़के-लड़की दोनों को सेहत के प्रति सजग बनाएं ताकि वे किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानी को छिपाएं नहीं बल्कि माता-पिता या घर में अन्य से साझा कर सकें। उसे इंडोर और आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रेरित करें। कैल्शियम से हड्डियों की मजबूती शरीर के अहम अंगों की कार्यक्षमता को बरकरार रखने के लिए बच्चे की डाइट में हाई प्रोटीन और कैल्शियम युक्त भोजन होना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग के लिए विटामिन-बी और सी से भरपूर चीजें जैसे केला, पपीता, संतरा, पालक, अंडे, शहद, फिश, दाल आदि ज्यादा लें। कैल्शियम और अन्य जरूरी न्यूट्रिएंट के लिए डाइट में दूध व दूध से बनी चीजें और सूखे मेवों को शामिल करें। मौसमी सब्जियां और फल शरीर की जरूरत को पूरा करने में सहायक होते हैं।

बैग कैरी करने का तरीका...

हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जिन्हे कैरी करने के तरीके से हमारी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है। इन्हीं चीजों में से एक है हमारे बैग कैरी करने की आदत। अगर आपको लगता है कि बैग को किसी भी तरह कैरी करो क्या फर्क पड़ता है, तो आपको इस बारे में एक बार और सोचने की जरुरत है। यही तरीका आपके बारे में बहुत कुछ कहता है।

बारिश के मौसम में हो सकती है स्किन एलर्जी

मानसून के इस सीजन में स्किन एलर्जी होने का बड़ा कारण है मॉइश्चर। नमी में कई तरह के बेक्टीरिया भी पैदा होते हैं, साथ ही हाउस डस्ट माइट की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। इसलिए इस समय घर और बाथरूम में सीलन न पैदा होने दें। धूप आने दें ताकि कीटाणु और फंगस खत्म हो जाएं और पर्दे, कारपेट, गिलाफ आदि को समय-समय पर धोते रहें।

सबकंजंक्टिवल हेमोरेज के क्या हैं कारण

जब छोटे, नाजुक ब्लड वेसल्स आंख के सफेद कवर के नीचे टिश्यु को चोट पहुंचने लगते है, तो आंख में लाली आ जाती है। और इसका अर्थ यह है कि आपको सबकंजंक्टिवल हेमोरेज हुआ है। यानी सबकंजंक्टिवल हेमोरेज आंख के सफेद हिस्से में प्रदर्शित होने वाला लाल चमकदार पैच है। यह समस्या कई समस्याओं में से एक है जिसे रेड आई कहा जाता है। सबकंजंक्टिवल हेमोरेज आमतौर पर अपनी विशिष्ट उपस्थिति के बावजूद भी किसी भी प्रकार की दृष्टि समस्याओं या आंख में असुविधा का कारण नही होता है।

आंख का सफेद भाग (श्वेतपटल) क्लियर टिश्यु की पतली परत के साथ कवर होता है, जिसे बल्बर कंजाक्टिवा कहा जाता है। सबकंजंक्टिवल हेमोरेज तब होता है, जब छोटे ब्लड वेसल्स खुल कर टूट जाते है और कंजाक्टिवा के अंदर बहने लगते है। यह ब्लड अक्सर दिखाई देता है, लेकिन जब तक यह कंजाक्टिवा के भीतर ही सीमित होता है तो इसे दूर और साफ नहीं किया जा सकता है। समस्या चोट के बिना होती है और अक्सर इसे पहली बार नोटिस उठने के बाद आईने के सामने आने से किया जाता है।

लेकिन आंखों की लाली आंख की अन्य गंभीर समस्याओं के प्रकार का संकेत हो सकता है। खासतौर पर अगर आपकी आंख से डिस्चार्ज हो रहा हो तो आंख की जांच के लिए अपने नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें। ताकी संक्रमण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया, वायरस या अन्य सूक्ष्मजीवों की जांच की जा सकें। अगर आपको आंखें में अचानक परिवर्तन के साथ लगातार लालिमा और दर्द या प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता का अनुभव हो तो तुरंत अपने आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें। इस तरह की आंखों में लाली अन्य प्रकार की आंख की समस्या जैसे अचानक मोतियाबिंद के शुरूआत का संकेत हो सकता है। आंखों में खून, सबकंजंक्टिवल हेमोरेज से आंख में ब्लड आमतौर पर एक या दो सप्ताह के भीतर गायब हो जाता है। हालांकि यह हमेशा समस्या के स्रोत की पहचान करने के लिए संभव नहीं है, लेकिन सबकंजंक्टिवल हेमोरेज के कुछ संभावित कारणों में शामिल हैं-

■ आंखों में चोट, ■ आंखों को मलना, ■ वायरल संक्रमण, ■ अचानक दबाव का बढ़ना जैसे छींकना या खांसना , ■ ब्लड को पतला करने वाली दवाएं, ■ हाई ब्लड प्रेशर, ■ आंख की सर्जरी जिसमें लेसिक और मोतियाबिंद सर्जरी शामिल है, ■ कम मामलों में रक्त के थक्के की समस्या या विटामिन की कमी विटामिन के रक्त के थक्के के कामकाज को बढ़ावा देने वाला आवश्यक प्रोटीन है। ■ सबकंजंक्टिवल हेमोरेज नवजात शिशुओं में बहुत ही आम है। ऐसा प्रसव के दौरान नवजात शिशुओं के शरीर पर दबाव में परिवर्तन के कारण होता है।

लक्षण

- इस समस्या के होने पर आंख के सफेद हिस्से में चमकदार लाल पैच आने लगते है।
- यह पैच दर्दरहित होता है।
- आंख से किसी प्रकार का डिस्चार्ज नहीं होता।
- आंखों की रोशनी पर भी असर नहीं पड़ता।

इलाज

सबकंजंक्टिवल हेमोरेज के लिए किसी भी इलाज की जरूरत नहीं होती है। बस आपके रक्तचाप की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। सबकंजंक्टिवल हेमोरेज आमतौर पर 2-3 सप्ताह के अंदर अपने आप ही दूर हो जाता है। लेकिन प्रभावित हिस्से पर खरोंच की तरह है, रंग बदल सकते हैं। आमतौर पर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में सबकंजंक्टिवल हेमोरेज बुजुर्ग व्यक्तियों में गंभीर वैस्कुलर डिस्ऑर्डर का संकेत हो सकता है।

ध्यान रहे

- समस्या होने पर लुब्रिकेट आई ड्रॉप आंखों को आराम पहुंचाने में मदद करते है, हालांकि यह आई ड्रॉप टूटी हुई ब्लड वेसल्स की मरम्मत में मदद नहीं कर सकते है।
- अगर आप खून को पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं तो इसे लेना तब तक बंद न करें जब तक आपका डॉक्टर आपको ऐसा न करने के निर्देश नहीं देता।
- आंखों को रगड़ने से बचें, क्योंकि सही शुरूआत के बाद यह फिर से खून बहने के खतरे को बढ़ा सकता है।

जानें क्या है ड्रेस सिंड्रोम

ड्रेस सिंड्रोम (ड्रग रश विध एओसिनोफिलिया एंड सिस्टमिक सिम्टम्स), एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया शब्द है, जोकि वर्तमान में 10 प्रतिशत तक की अनुमानित मृत्यु दर के साथ एक अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक दवा के लिए गंभीर, विशेष स्वभाव वाला मल्टीसिस्टम प्रतिक्रिया होती है। ड्रग रश विध एओसिनोफिलिया एंड सिस्टमिक सिम्टम्स (DRESS), एक ऐसा सिंड्रोम है, जो कि कुछ दवाओं के कारण होता है, जिनके चलते आंतरिक अंगों की सूजन, दाने, बुखार, लिम्फाडेनोपैथी तथा हेमटोलॉजिकल असामान्यताएं जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आदि होते हैं। इस सिड्रोम में मृत्यु दर दल प्रतिशत तक होती है। इसके उपचार में जोखिम पैदा करने वाली दवा को के प्रभाव को रोका जाता है और सहायक देखभाल उपलब्ध कराई जाती है।

लक्षण और निदान

ड्रेस सिंड्रोम का प्रभाव सबसे अधिक, नुकसान पहुंचाने वाली दवा के प्रभाव शुरू करने के दो से आठ सप्ताह बाद प्रकट होता है। इस दवा का प्रभाव एक दिन के भीतर दोबार भी हो सकता है। प्रारंभिक सुधार के बाद भी इसके लक्षण दवा को रोकने के बाद तीन से चार सप्ताह के भीतर दोबारा भड़क सकते हैं। रोग में मरीजों को नियमित रूप से जल्दी-जल्दी बुखार आता है, और चकत्ते भी विकसित हो जाते हैं। ये लक्षण हल्के से दाने से लेकर फफोले पड़ने तथा त्वचा निकलने तक हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर इसमें खुजली, या धब्बेदार पर्विल होता है, जोकि छोटे व बड़े दाने तथा वेसिक्लेस पैदा कर सकता है। लगातार बदलते लक्षणों की वजह से सिंड्रोम के निदान में मुश्किल हो सकती है। इस तरह के दाने, बुखार, और ऑर्गन इंवाल्वमेंट जैसे लक्षण अन्य कई कारणों की वजह से भी हो सकते हैं। इसके निदान में निम्न चरण शामिल हो सकते हैं-

- अस्पताल में भर्ती करना
- रिएक्शन दवा संबंधित होने का संदेह
- त्वचा पर लाल चकत्ते
- 38 डिग्री सेल्सियस तक बुखार
- दो स्थलों पर बढ़े हुए लिम्फ नोड्स
- कम से कम एक आंतरिक अंग की भागीदारी

ड्रेस सिंड्रोम के कारण

वे दवाएं जिनकी वजह से ड्रेस सिंड्रोम होता है, में फेनोबार्बिटल, कार्बमाजेपाइन, फेनीटोइन, लैमोट्रिन, मिनॉयक्लीन, सुल्फोनमीडेस, एलोप्यूरिनॉल, मोडेफिनिल तथा डाप्सोन आदि शामिल हैं। इस सिड्रोम के साथ HHV6 को भी संबद्ध किया गया है।

CAREER

योग्यता के साथ ही टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल भी जरूरी

नौकरी के लिए सिर्फ डिग्रियां ही काफी नहीं

अच्छी नौकरी पाने के लिए केवल डिग्रियां ही काफी नहीं इतना तो सभी जानते हैं कि केवल डिग्रियां एक अच्छी नौकरी दिलवाने के लिए काफी नहीं होती हैं। केवल उच्च शिक्षा हासिल करके आप यह भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आपको रोजगार जरूर मिल जाएगा। आज के प्रतियोगी युग में एक अच्छी नौकरी सुनिश्चित बनाने के लिए आवश्यक है कि युवा विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं के साथ-साथ टेक्निकल व सॉफ्ट स्किल्स में भी माहिर हों। तभी उनको अन्य आवेदकों के मुकाबले तरजीह दी जा सकेगी।

व्यक्तित्व निखारें...

हर वर्ष बड़ी संख्या में युवा देश भर के शैक्षिक संस्थानों से डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश में निकलते हैं। ऐसे में उनमें सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट करने पर भी काफी जोर दिया जाने लगा है। कारोबारी तथा मूल शिष्टाचार, ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज तथा कोऑर्डिनेशन स्किल्स किसी भी इंटरव्यू में बड़ा अंतर डाल सकते हैं। इन दिनों कंपनियां अपने कर्मचारियों में पेशेवर कौशल के अलावा व्यावहारिक कौशल की मांग भी करती हैं। क्लाइंट्स तथा टीम सदस्यों से मेल-मिलाप तथा तालमेल के साथ काम करने के लिए ये कौशल बेहद जरूरी माने जाते हैं। इनमें दक्ष व्यक्ति काम के दबाव तथा तनाव को बेहतर ढंग से झेल सकता है और इससे आपके व्यक्तित्व में भी काफी निखार आता है।

नई भाषा सीखें...

आज वैश्विक स्तर पर काम करने के मौके पहले से कहीं अधिक हैं। ऐसे में यदि आपको देश-विदेश की कोई अतिरिक्त भाषा का ज्ञान है तो आपके लिए नौकरी पाने के मौके भी उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में तो विदेशी भाषा का ज्ञान रखना एक विशिष्ट योग्यता मानी जाती है।

ऑनलाइन इमेज से होगा फायदा

इन दिनों नियोक्ता सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर उम्मीदवारों के अकाउंट्स को भी देख सकते हैं। इनकी मदद से उन्हें उम्मीदवारों के व्यक्तित्व या व्यवहार के बारे में कुछ हद तक जानकारी मिल जाती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप वहां ऐसी जानकारी दें जो आप नियोक्ता को आपकी खूबियों के बारे में बता सकें। अच्छे ग्रुप्स से आपका जुड़ा होना भी नियोक्ताओं को प्रभावित कर सकता है। खुद के भीतर खासियत पैदा करने में इंटर्नशिप विशेष रूप से मददगार साबित हो सकती है। यदि आपके कॉलेज की ओर से आपको इंटर्नशिप के मौके दिए जाते हैं तो इसका पूरा-पूरा लाभ उठाएं। अपनी ओर से भी किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया जा सकता है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।

समुद्र की लहरों के बीच कॅरियर की उड़ान

तकनीक और विज्ञान ने आज संसार को इतना छोटा बना दिया है कि हम पूरी दुनिया को कुछ ही घंटों में नाप सकते हैं। समुद्र के जरिए ऐसा करना बेहद रोमांचक होता है। अगर आप भी समुद्र के जरिए दुनिया नापने का सपना देखते हैं, रोमांचित होना चाहते हैं तो आपके लिए अवसर की कमी नहीं है। यह फील्ड है मरीन इंजीनियरिंग। इसके तहत जहाज बनाने और इसकी मरम्मत करने, जहाज के रख-रखाव तथा इसकी सुरक्षा शामिल होती है। इन सबको करने के लिए क्वालीफाइड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। एक नेवल आर्कीटैक्चर के तहत ये सारे कार्य आते हैं।

प्रमुख संस्थान...

- इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई
- हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ नॉटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिकंदरा राव, उप्र
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट, कोलकाता
- तुलानी मेरीटाइम इंस्टीट्यूट, पुणे
- आरएल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉटिकल साइंसेज, मदुरै

योग्यता...

नेवल आर्कीटैक्ट के तौर पर कॅरियर बनाने के लिए अंडरग्रैजुएट और पोस्ट गैजुएशन कोर्स उपलब्ध हैं। अंडरग्रैजुएट कोर्स के तहत बी. टेक मरीन इंजीनियरिंग, बी. टेक नेवल आर्कीटैक्चर एवं ओशिन इंजीनियरिंग, बी.एससी शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर, बीएससी नॉटिकल साइंस के अलावा डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। वहीं मरीन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री कोर्स भी हैं, जैसे पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट में एमबीए, इंटरनेशनल ट्रांस्पोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में एमबीए, नेवल आर्कीटैक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग में एम. टेक।

कार्यक्षेत्र एवं आमदनी...

इंजीनियरिंग की एक नई ब्रांच के तौर पर शिप बिल्डिंग और इससे जुड़े क्षेत्र में कॅरियरकी अपार संभावनाएं हैं। नेवल आर्कीटैक्चर, शिप बिल्डिंग और शिपिंग टेक्नोलॉजी के तहत शिप डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटीनैंस, और समुद्री मार्ग पर यातायात आदि में इस्तेमाल होने वाले साधनों, मसलन जहाजों और पनडुब्बियों की मरम्मत का काम सिखाया जाता है।

रेसिपी

क्रीमी कोर्न समोसा

सामग्री

1 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 1 कप दूध, 1/2 कप बेबी कॉर्न(कटे हुए), 1/2 कप शिमला मिर्च लाल,पीली,हरी, 1 बड़ा चम्मच चीज, तलने के लिए तेल, नमक स्वादानुसार, मिर्च

विधि

सबसे पहले मैदा और नमक छान कर तेल डाल कर पानी से गूंध लें। एक कढाई में मक्खन गरम कर मैदा भूनें व इसमें दूध डालकर व्हाइट सॉस बनाएं। अब इसमें कटी शिमला मिर्च व बेबी कॉर्न,नमक और मिर्च डाल कर 1-2 मिनट तक पकाएं और चीज को कद्दूकस करके डालें और आंच से उतार लें। इसके बाद मैदा की छोटी-छोटी लोइयां बना कर पूरी बेल कर बीच में से आधी काट कर समोसे की शेप दें। अब इसमें पहले से बनाकर रखी हुई व्हाइट सॉस का मिश्रण भर कर पानी की सहायता से उंगुलियों से दबाते हुए बंद कर दें। एक कडाही में तेल गर्म करके इसमें समोसे तल लें और गर्मा-गर्म सॉस के साथ सर्व करें।

मेथी लीव्स् साम्भर

सामग्री

1 कप कटी हुई मेथी, 1 कप तुवर दाल , धोकर छानी हुई, 1/2 कप बारीक कटे हुए टमाटर, 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 कप कटा हुआ कद्दू, 1/2 कप कटी हुई लौकी, 1/4 टी-स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वादअनुसार, 1/2 कप सहजन की फल्ली , 2 के टुकड़ो में कटी हुई, 2 टी-स्पून तेल, 1 टी-स्पून सरसों, 5 कड़ी पता, 1 टी-स्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टेबल-स्पून साम्भर मसाला, 1 टेबल-स्पून नींबू का रस

विधि

तुवर दाल, टमाटर, प्याज़, कद्दू, लौकी, हल्दी पाउडर, नमक और 3 कप पानी को एक प्रैशर कुकर में अच्छी तरह मिला लें और 3 सिटी के लिए प्रैशर कुक कर लें। ढक्कन खोलने से पूर्व सारी भाप निकलने दें और एक तरफ रख दें। सहजन फल्ली और 1/2 कप पानी को एक गहरे नॉन-स्टिक पैन में मिलाकर, मध्यम आंच पर 5 मिनट के लिए पका लें। बिना छानें एक तरफ रख दें। दुसरे नॉन-स्टिक पैन में तेल गरम करें और सरसों डालें। जब बीज चटकने लगे, कड़ी पत्ता और मेथी डालकर अच्छी तरह मिला लें और मध्यम आंच पर, बीच-बीच में हिलाते हुए, 2 मिनट के लिए पका लें। लाल मिर्च पाउडर, साम्भर मसाला, पानी के साथ पकी हुई सहजन फल्ली, पके हुए दाल का मिश्रण, थोड़ा नमक और 1/2 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें और, बीच-बीच में हिलाते हुए, मध्यम आंच पर 5 मिनट के लिए पका लें। नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें। गरमा गरम परोसें।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**